

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

5 सितम्बर, 1985

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भुक्रवार, 27 सितम्बर , 1985

पृष्ठ संख्या

सदस्य द्वारा भाषण/प्रतिज्ञान	(2)1
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)23
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)25
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(2)25
वाक आरूढ	(2)37
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	
श्री श्रीकिशन दास द्वारा	(2)38
(I) मुख्य मंत्री द्वारा पंजाब समझौते तथा राज्य की राजधानी के स्थान के चयन तथा सुरक्षा अमले द्वारा विधायकों की तलाशी सम्बन्धी	(2)38
(Ii) राजस्व राज्य मंत्री द्वारा जिला महिन्द्रगढ़ और भिवानी में फसल के हुए नुकसान सम्बन्धी	(2)46
सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स फर्स्ट इन्स्टालमेंट 1985-86 पर चर्चा तथा मतदान।	(2) 52

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 27 सितम्बर , 1985

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

सदस्य द्वारा भापथ/प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर, अब 25 सितम्बर, 1985 को हुई बाई इलैक्शन में इलैक्ट हुए मैम्बर की ओथ आफ अफरमेंट इन अकार्डिंग टू कास्टीच्यूशन होगी। श्री श्री किशन दास।

Shri Sri Krishan Dass, the member who had been returned from 30- Rohtak Assembly constituency, then made the prescribed oath/affirmation of allegiance to the Constitution, signed the roll of members and took his seat in the House.

तारांकित प्रश्न एवम उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहिबान, अब सवाल होंगे। पहला सवाल 1029, श्री राम बिलास भार्मा का है।

Recruitment made by the Haryana State CO-operative Land Development Bank

***1029. Shri Ram Bilas Sharma:** Will the Minister of State for Co-operation be pleased to state-

(a) the total number of employees working at present on permanent, temporary and daily wages basis in the Haryana State Co-operative Land Development Bank, Chandigarh separately:

(b) the number of Class IV employees out of the employees referred to in part (a) above together with the names and permanent addresses thereof;

(c) the category wise number of employees out of the employees mentioned in part (a) above, recruited during the period from May, 1982 to June, 1985; and

(d) the criteria adopted for the recruitment of the employees as referred to in part (c) above ?

श्री अध्यक्ष: इसके जवाब के लिए गवर्नमेंट ने एक्सटै इन मांगी है, जो मैंने दे दी हैं।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, यह मेरा सवाल है और मुझे इसका जवाब लिखित में मिला है। इसका जवाब तो गवर्नमेंट ने दे रखा है, फिर एक्सटै इन किस बात को दी गई है ?

श्री अध्यक्ष: यह जवाब कम्पलीट नहीं है। गवर्नमेंट ने 10 दिन की एक्सटै- इन मांगी है, which I have allowed. इस बारे में सम्बन्धित मंत्री से आया इस प्रकार है—

@ Interim Reply

“D.O No. 216-C-VILL-85/29106

State Minister,

Piara Singh,
Haryana

Cooperation Department

Chandigarh

Dated September 26,

1985.

Dear Shri Tara Singh Ji,

Kindly refer to the Starred Assembly Question No. 1029 asked by Shri Ram Bilas Sharma, M.L.A regarding recruitment made by the Haryana State Cooperative Land Development Bank, which is due for answer in the Haryana Vidhan Sabhan on 27-9-1985.

2. In this connection I am to inform you that the desired information is beign collected from the Bank and there is possility for it to tke some more time. It is, thereofore, requested that an extension for 10 days may please be accorded.

With regards

Your Sincerely,

Sd/-

(Piara Singh)

Shri Tara Singh

Speaker, Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

तारांकित प्र न सख्या 1034

यह प्र न पूछा नही गया क्योकि इस समय माननीय सदस्य, चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल, सदन मे उपस्थित नही थे ।

Mini Stadium at Ballabgarh

***1021. Shrimati Sharda Rani:** Will the Minister of State for Trasnport be pleases to state-

(a) whether the construction work of a mini stadium at Ballabgarh is in progress at present together with the date on wchich the said construction work was started: and

(b) If reply to part (a) above is in the affirmative the amout of expenditurs incurred there on to date togerherwith the time by which the constructions thereof is likly to be completed ?

परिवहन राज्य मंत्री(चौधरी चन्दा सिंह)

(क) नही ।

फिर भी, निर्माण कार्य 20.8.1976 को आरम्भ हुआ और बाद में यह निर्माण कार्य बंद कर दिया गया क्योंकि यहां एक बड़ा स्टेडियम बनाए जाने का निर्णय लिया गया था।

(ख) रुपये 134880.

संशोधित परियोजना पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना है। अतः इस स्टेडियम को पूर्ण करने पर कितना समय और लगेगा, इसके बारे में नहीं बताया जा सकता है।

श्रीमती भारदा देवी: अध्यक्ष महादेय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के (क) भाग का उत्तर दिया है नहीं। इससे आगे लिखा है कि इस स्टेडियम का निर्माण कार्य गति में था। आप देखें, इन्होंने खुद लिखा है—

“However, the construction was started on 20-8-1976, but later on it was stopped...”

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने सवाल में यह बात पूछी थी

—

“Whether the construction work of a mini stadium at Ballabgarh is in progress at present...?”

इस में मैंने पूछा कि क्या इस स्टेडियम का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है? इन्होंने इसका उत्तर दिया नहीं और इसके आगे यह लिखते हैं—

“फिर भी निर्माण कार्य 20.8.1976 को आरम्भ हुआ और बाद यह निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया, क्योंकि यहां एक बड़ा स्टेडियम बनाये जाने का निर्णय लिया गया था”

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे एक सबमिशन है कि मेरे सवाल का जो उत्तर है इसको तोड़ा मरोड़ा न जाए, जो सवाल है उसका सही जवाब दिया जाए। इन्होंने उत्तर में यह बात कही कि निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया। मैं जानना चाहती हूँ इस स्टेडियम के अधूरा रहने के क्या कारण हैं? यह स्थान बहुत गन्दा है और वहां पर कई अनियमितताएं हो रही हैं। सारा स्टेडियम बुरी हालत में पड़ा है। मंत्री महोदय ने खुद बताया कि इस पर अब तक 138880 रूपया खर्च किया गया। जब इतना पैसा खर्च हो चुका है तो थोड़ा सा और पैसा खर्च करके इस स्थान को ठीक ढंग से बनाये। इस स्थान पर कबड्डी का खेल हो सकता है, क्योंकि यहां पर कबड्डी का बहुत बड़ा मेला होता है। कबड्डी खेलने वाले बच्चों का अभ्यास करवाने के लिए इस स्टेडियम की डिवलपमेंट की जा सकती है। क्या मंत्री महोदय का इस स्टेडियम को सही ढंग से बनाने का कोई इरादा है ?

श्री चौधरी चन्दा सिंह: स्पीकर साहब, जो जमीन वक्फ बोर्ड की पडी थी वह इस स्टेडियम के लिए सरकार ने ले ली है। पैसे की कमी के कारण या किन्हीं और कारणों के कारण यह स्टेडियम नहीं बन सका, वैसे भी यह बहुत पहले का मामला है जिसकी वजह से इसकी स्वीकृति भी लैप्स हो गई थी। फिर दोबारा

सैव इन 4 और 6 के तहत नोटिफिके इन जारी कर के एक्वायर करने जा रहे है, ज्यो की स्वीकृति मिलेगी एक्वायर कर लेगे। इसके लिए पैसा भी है। इस स्टेडियम को फरीदाबाद कम्पलैक्स और खेल विभाग दोनो मिलकर इसी व्यवस्था ठीक करेगे। सारी औपचारिकताए पूरी करके ही इस पर दोबारा काम भुरू किया जा सकेगा। यह स्टेडियम भायद उस वक्त भुरू किया हुआ था जब भारदा जी मंत्री थी, लेकिन बाद मे परिस्थितियां बदलती चली गई। अब इस पर तेजी के साथ काम करने और इसकी व्यवस्था ठीक करने के लिए फरीदाबाद कम्पलैक्स और खेल विभाग दोनो जागरूक हैं।

श्री निहाल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि जंहा पर स्टेडियम कस्ट्रक्ट किये जाते है, उनकी क्या भारते होती है ? स्टेट मे स्टेडियम कस्ट्रक्ट करने का क्या आईटेरिया है? इसके इलावा मिनी स्टेडियम और फुल स्टेडियम मे क्या फर्क है? क्या मिनी स्टेडियम मैम्बर का साईज देख कर बनाये जाते है या भाहर देख कर बनये जाते है ?(हंसी)

चौधरी चन्दा सिंह: स्टेडियम का किसी मैम्बर के आकार से कोई मतलब नही है यह तो खुदा जाने वह मैम्बर कैसा बना है। जहा स्टेडियम बनाया जाता है वहा की आव यकता को देखा जाता है आव यकता को देख कर स्टेडियम की भी बनाया जा सकता है इसके लिए गवर्नमैट आफ इडिया और स्टेट गवर्नमैट दोनो सदन देती है

श्री अध्यक्ष: इन्होंने तो मिनी स्टेडियम और फूल स्टेडियम का डिफ्रेस है। आप डिफ्रेस बता दीजिए।

चौधरी चन्दा सिंह: जो बड़ा स्टेडियम होता है उसकी कौस्ट 50 लाख लगभग आती है और मिनी स्टेडियम 50 हजार रूपये से भी बन जाता है। किसी जगह पर मिनी स्टेडियम बनाने का आईटेरिया यही है कि गांव की पचायत 4 एकड़ जमीन के साथ 10 हजार रूपया स्टेडियम बनाने के लिए दे दे। इसके बाद जितना खर्चा आयेगा, उसका आधा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट और आधा गवर्नमेंट आफ इंडिया देगी। यह आईटेरिया जिला स्तर पर खेले विभाग द्वारा स्टेडियम बनाये जाने का है। जिला स्तर पर लोगो के पास इतने साधन नहीं हैं इस परपज के लिए जिला स्टेडियम कमेटी बनाई हुई है जो जिलाधी 1 के अधीन है। यह कमेटी जिला स्तर पर स्टेडियम खोलने के लिए साधन जुटाली है। कुछ मदद गवर्नमेंट आफ इंडिया देती है। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट देती हैं।

चौधरी कुन्दल लाल: स्पीकर साहब, सफीदो सब डिवीजन मे खेल विभाग की तरफ से क्या कोई स्टेडियम बनाने का विचार है अगर विचार है तो वह स्टेडियम कब तक बनाया जाएगा ?

चौधरी चंदा सिंह: अध्यक्ष महोदय, हर जगह और हर जिला स्तर पर अपने साधनों के मुताबिक नए स्टेडियम बनाने की योजना है। इनके यहां मैं खुद गया था। और इनसे कहा था कि

औपाचारिकताएं पूरी कराएं। अब चूंकि इस बारे में प्रश्न नहीं है इसलिए बाद में पता करके मैं व्यक्तिगत तौर पर इनको सारी स्थिति बता दूंगा।

चौधरी फूल चन्द: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने एलीकेटन के हिसाब से स्टेडियम और मिनी स्टेडियम का डिफरेंस तो बता दिया लेकिन वे कैपसिटी के हिसाब से भी इनका डिफरेंस बताएंगे? क्या ये यह भी बतायेंगे कि प्रान्त में कहा कहा मिनी स्टेडियम और कहा कहा स्टेडियम बन रहे हैं?

चौधरी चन्दा सिंह: स्पीकर साहब, मैंने सवाल चुकि बल्लभगढ़ के बारे में था इसलिए इस वक्त यह जवाब देना मुश्किल है।

श्री एस.सी. चौधरी: स्पीकर साहब, मैं आपका माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि मिनी स्टेडियम, बल्लभगढ़ की उस जमीन पर जो वक्फ बोर्ड की है और उसमें कब्रें हैं तथा मुसलमान भाईयों ने उसके बारे में काफी एतराज किया है? भायद इसी वजह से वह स्टेडियम नहीं बन पा रहा है। अगर मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं तो क्या वे मुसलमान भाईयों की बात को मानेंगे और इलाके की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और जगह स्टेडियम का काम तेजी से पूरा करवाएंगे?

चौधरी चन्दा सिंह: अभी तक यह बात मेरे नोटिस में नहीं आई है। इसको देख लेंगे। हो सकता है देरी के कारणों में से एक कारण यह भी रहा हो। चौधरी साहब चूँकि अब इस बात को मेरे नोटिस में लाए हैं, इसको देख लेंगे तथा जिस तरह की कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी, सरकार उसे जरूर करेगी। पहले हो यह काम काफी देर से रूका पड़ा है। अगर फिर से स्वीकृति लेने की बात हुई तो और देर हो जाएगी।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने अभी बताया कि स्टेडियम को बनाने से पहले प्रोजेक्ट स्कीम और साइट प्लान आदि तैयार की जाती है और उसकी स्वीकृति के बाद काम शुरू किया जाता है। इन्होंने यह भी बताया कि जिस स्टेडियम की एलोकेशन 50 रुपये तक हो उसे बड़ा स्टेडियम कहते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया और हरियाणा गवर्नमेंट दोनों मदद देते हैं मैं मंत्री महोदय जी ने जानना चाहुंगा कि क्या इनके नोटिस में ऐसे कैंसिज है जिनमें एक साल तो मिनी स्टेडियम बनाने का काम एक जगह शुरू किया जाता है लेकिन नैक्सर ईयर उस जगह को छोड़ कर उसी भाहर में दूसरी जगह पैसा देकर काम शुरू किया जाता है और तीसरे साल उस जगह को छोड़कर काम को पहली जगह ही में ट्रांसफर कर दिया जाता है? इस तरह का एक केस रोहतक का है। मैं मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहुंगा कि इस तरह से साइट बदलने का इनका पैमाना

क्या है? क्या ये काम भुरु करने से पहले फाईनल फ़ैसला नही ले पाते ?

चौधरी चन्दा सिंह: ऐसा कोई केस मेरे नोटिस मे नही है लेकिन चौधरी साहब जहां के बारे मे कहेगे पता करवा लेगे। स्पीकर साहब, हमारी प्रगति गील स्टेट है। जहां पहले ब्लौक थे वहां अब तहसील बन गई है, सब डिविजन बन गए है और कई जगह जिले बन गए हैं। यहां पर हर तरह से प्रगति हुई है। सरकार के अधिकारी और जिले का प्र गसन सारी बातों को देख कर फ़ैसला लेता है। अध्यक्ष महोदय आप जानते है कि जब व्यक्ति काम करता है। और ज्यादा काम करता है तो कई बार उससे भूल भी हो जाती है।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मै तो इनसे केवल इतना जानना चाहता हू कि रोहतक मे पहले साल तो इन्होने एक जगह स्टेडियम बनाने के लिए पैसार दे दिया और दूसरे साल दूसरी जगह के लिए पैसा दे दिया। यह कैसे हो गया ?

श्री अध्यक्ष: चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी आप तो काबिल मैम्बर है। आप जानते है कि सवाल बल्लभगढ के बारे मे है। इसलिए ये रोहतक या हिसार के बारे कैसे जवाब दे सकते है ?

Chaudhri Surender Singh: My main question concerns with the project plan.

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मैं देता हूँ रोहतक के बारे में उन्होंने कहा कि पहले साल तो स्टेडियम बनाने के लिए पैसा एक जगह से लिए दिया, लेकिन दूसरे साल किसी और जगह के लिए दे दिया और तीसरे साल फिर पहले वाली जगह पर काम कर दिया। स्पकीर साहब, ऐसी बात नहीं है। रोहतक में जो सिलैक्ट की गई थी उसी जगह पर काम तेजी से चालू है। मैं समझता हूँ कि वह स्टेडियम 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा।

मास्टर विठ्ठल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जवाब देते हुए कहा कि बड़ा स्टेडियम 50 लाख रुपये तक की लागत का होता है और छोटा स्टेडियम 50 हजार रुपये तक की लागत का होता है। क्या वे बताएंगे कि यह स्टेडियम छोटा है या बड़ा है क्योंकि इस पर अभी तक 134850 रुपये का खर्च हो चुके हैं? क्या ये यह भी बताएंगे कि पैसे को ठीक तरह से प्रयोग न करने की जिम्मेवारी किस पर डालेंगे क्योंकि माननीय सदस्य ने अभी यहां बताया कि उस स्टेडियम की ऐसी हालात हैं जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता?

चौधरी चन्दा सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कहा है कि ज्यों ही जमीन बगैरा की औपचारिकताएं पूरी होंगी यह काम हो जाएगा लेकिन माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मंत्री अब बना हूँ यह काम तो सन् 77 से बन्द पड़ा है। उस समय यहां जनता सरकार थी और मेरे भाई भायद उसमें थे इनको

भायद यह भी पता होगा कि स्वीकृति क्यो लैप्स हुई। हमारे आने के बाद तो वक्फ बोर्ड की जमीन ऐक्वायर करने के लिए कार्यवाही भुरू हुई है। जैसे ही जमीन ऐक्वायर हो जाएगी स्टेडियम बनाने के लिए तारीख भी निश्चित कर दी जाएगी। आप जानते है जैसा अभी ए0सी0 चौधरी जी ने कहा कि कई बार लोगो के रिप्रेजैन्टे टान आ जाते है। कई बार लोग मुख्यमंत्री जी से मिल लेते है कि फंला जगह ठीक नही दूसरी जगह स्टेडियम बनना चाहिए। जिलाधी टा पर भी कई लोग दबाव डालते है कि स्टेडियम यहा नही बनना चाहिए। प्रजातंत्र मे लोगो की बातो की तरफ ध्यान देना पडता है। जिलाधी टा लोगो की रया के मुताबिक साइट मे थोडी बहुत आल्ट्रे टान कर लेता है। इसलिए मै माननीय सदस्य को बताना चाहता हू कि सरकार की तरफ से काम करने मे कोई ढील नही है।

श्री फतेह चन्द विज: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा कि रोहतक मे बडी तेजी के साथ काम भुरू है। क्या ये बताएगे कि यह तेजी एक हफ्ते से ही भुरू हुई है या उससे पहले भी थी ?

चौधरी भजन लाल: मै यह मानता हू कि पहले की जिम्मेवारी भी हमारी है लेकिन आपके नेता ने कभी इसकी चर्चा नही की। अब हमने इन सब बातो को देखा है और 6 महीने के बाद रोहतक की भावल बदल कर दिखाएगे।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक बल्लभगढ के स्टेडियम का सम्बन्ध है अभी चौधरी चन्दा सिंह जी ने बताया कि उसके लिए जमीन एक्वायर करने जा रहे हैं। मैं भी मैम्बर्ज की तसल्ली के लिए बता देना चाहता हू कि जमीन बहुत जल्दी ही ऐक्वायर करके काम चालू कर देगे

ताराकित प्रान स0 1037

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल सेठ रामदास धमीजा का है।
He is not present, so this question is not put.

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, अभी क्वै चन आवर का पौना घन्टा टाइम रहता है और जिन मैम्बरान ने सवाल पूछा है उन मे से कई नहीं आये है इसलिए उनके सारे क्वै चन्ज रह जायेगे। अगर आप उन्हे पूछने की परमिान दे तो ठीक रहेगा। पहले भी ऐसा करते रहे है।

श्री अध्यक्ष: विज साहब, आपने तो रूलज आफ प्रोसीजर एन्ड कन्डक्ट आफ् बिजनैस की किताब देख रखी है, मुझे उसके मुताबिक ही चलना पडता है अगर आपके पास किसी मैम्बर की अथोरिटी है तो मुझे बता दे, मैं इजाजत दे दूंगा वरना नहीं।

ताराकित प्रान स0 1037

यह प्रान पूछा नहीं गया क्योकि इस समय माननीय सदस्य, चौधरी कुलबीर सिंह मलिक सदन में उपस्थित नहीं थे

ताराकित प्रान स0 999

यह प्रान पूछा नही गया क्योकि इस समय माननीय सदस्य, डा0 भीम सिंह दहिया सदन में उपस्थित नही थे

Water Connections given under Rural Water Supply Schemes

***1017 Chaudhri Surender Singh:** Will the Minister for Public Works Public Health be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the Government has started giving water connections to the private individuates in their houses under Rural Water supply scheme and

(b) if so, the total number of such connections given in District Bhiwani together with the details of terms and conditions, if any, on which such connections have been given?

जन स्वास्थ्य मंत्री(श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) सरकार ग्रामीण जल वितरण योजनाओ के अन्तर्गत निजि पानी के कनैकान देती आ रही है।

(ख) 247 अनुबन्ध क पर वह निबन्धन तथा भार्ते जिन पर निजि पानी के कनैकान स्वीकृत किए जाते है, विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत है।

जिन भार्ते पर पानी के निजि कनैकान दिए जाते है, का ब्यौरा

1. 6 मिलीमीटर से अधिक का फैसले कनैव इन नहीं दिया जायेगा।

2. प्रत्येक फैसले कनैव इन का फीस 50 रू0 होगी।

3. फैसले पाईप तथा अन्य सामान का प्रबन्ध उपभोगता द्वारा स्वयं अपने खर्चे पर करना होगा।

4. पहले नल के 10 रू0 माह तथा अतिरिक्त दूसरी टूटी के 5 रू0 प्रति मास लिए जाएंगे।

एक कनैव इन से दो नलको से अधिक की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5. पानी की खपत का खर्चा त्रैमासिक देना होगा। यदि बिल देने के 30 दिन के अन्दर अन्दर उसका भुगतान न किया गया, तो कनैव इन काट दिया जायेगा।

6. सरकार किसी भी समय बिना कोई कारण बताये पानी का कनैव इन काट सकती है।

7. पानी की खपत 45 एल.पी.सी.डी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8. प्रार्थी को गन्दे पानी की निकासी का प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

9. प्रार्थी को उपरोक्त निबन्धन एवम भातों को पूरा करने के लिए नान जूडिं गिल पेपर पर लिख कर देना होगा ।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि सरकार ने नौ कन्डी गन्ज लेड डाउन की है उनको मधेनजर रखते हुए प्राइवेट वाटर कनेक्ट गन्ज दिए जाते हैं । स्पीकर साहब, रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के तहत दस लिटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से पानी दिया जाता है । लेकिन इन्होंने अपने जवाब में बताया है कि जिन को प्राइवेट कनेक्ट गन्ज दिये जाते हैं उन्हें 45 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से सप्लाई होगी । क्या मंत्री जी बतायेगी कि अगर सभी घर गावों में यानी जितनी आबादी है, सब के सब प्राइवेट कनेक्ट गन्ज मांगे तो क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट लैबल पर सभी गांव वालों को इन्डीविजुअल लैबल पर कनेक्ट गन्ज दे देगी ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, सारे ही प्राइवेट कनेक्ट गन्ज 1127 के करीब दिये हुए हैं इनमें से 58 को छोड़ कर बाकी सब के सब हरियाणा बनने से पहले के दिये हुए हैं । सन् 1966 से अब तक केवल 58 कनेक्ट गन्ज दिये हैं । विभाग एक चीज के लिए प्रोग्राम बना रहा है कि जहां पर पानी अवेलेबल है और 75 प्रति सै लोग इन्डीविजुअल कनेक्ट गन्ज के लिए एप्लाई करते हैं और गाव की गली में कीचड बगैरहा ने होने का प्रबन्ध करने और साथ ही अन्दर की फिटिंग का इन्तजाम करना पचायत मान ले तो सरकार कनेक्ट गन्ज देने का इन्तजाम कर सकती है । सरकार

अभी थोड़े से गावों में एक्सपैरिमेंट करना चाहती है अगर पूरा गांव वाटर कनेक्ट इन के लिए एप्लाइ करेगा तो वहां पर प्राथमिकता दी जायेगी। अगर यह एक्सपैरिमेंट कामयाब हो जाये तो फिर जहां भी जरूरत होगी यानी जहां से भी मांग आयेगी उनको कनेक्ट इन्ज दिये जा सकते हैं सरकार ने एक चीज महसूस की है और पता तो एक्सपैरिमेंट से लगेगा क्योंकि देखभाल का खर्चा काफी हो जाता है अगर 75 परसेंट लोग एप्लाइ कर दे तो मेनटेनेन्स का खर्चा निकल सकता है। इसलिए एक्सपैरिमेंट करने का विचार किया है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस प्रकार की रिक्वेस्ट या एप्लीके इन्ज कितने गांवों से आयी है। जिनको ये सुविधाये जुटायी जायेगी ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी अभी तक मेरे पास सीधी एप्लीके इन्ज नहीं आई है। कुछ दिन पहले ही डिपार्टमेंट से फैसला किया था कि अलग अलग सर्कल्ज से एप्लीके इन्ज मंगवा ली जाये। जिन गांव से 75 परसेंट लोग एप्लाइ कर दे उन गावों के बारे में जल्दी से जल्दी फैसला करके कनेक्ट इन्ज दे दे। अगर भाई भले राम जी भी ऐसी एप्लीके इन्ज दिलवायेगे तो प्रायनिटी दे कर वहां भी वाटर कनेक्ट इन करवा देगे। मैं समझती हू कि यह सारा तजर्बा होने के बाद ही पता चलेगा कि हम कामयाब रहते हैं या नहीं।

चौधरी साहब सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, गावों के बहुत सारे लोग प्राइवेट कनैक्टान्स लेने के तैयार हैं। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसका क्या प्रोसीजर है? अगर 75 परसेंट न लेना चाहे और कुछ लोग चाहे और वे खर्चा भी देने के लिए तैयार हों तो क्या उन्हें प्राइवेट तौर पर कनैक्टान्स मिल जायेंगे?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: अगर कुछ लोग ही लेना चाहते हैं तो उनकी ही सारा खर्च देना पड़ेगा क्योंकि पांच हजार या पाच हजार से ऊपर की पापुलेशन का जो गांव है उस की गलियों में पाइप लाइन बिछा दी जाती है तो छोटे गांव हैं उनकी पाइप लाइन फिरनी तक ही रह जाती है। इस के आगे कोई भी अकेला आदमी गांव में पाइप नहीं ले जा सकता। अगर कोई ऐसा आदमी है जो पाच दस हजार रूपया खर्च कर सकता है और पूरी फिटिंग भी करवा सकता है तो हम उसे कनैक्टान्स दे देंगे।?

चौधरी अजमत खा: क्या सरकार ने कोई ऐसे आदेश जारी किये हैं कि अगर पाच सौ दरखास्ते आ जायें या 75 प्रतिशत लोग एप्लाइ कर दें तो उन्हें कनैक्टान्स दे देंगे? मेरे हल्के से तीन गांवों की पाच पाच सौ दरखास्ते आयी हुई हैं क्या उन्हें कनैक्टान्स मिलेंगे।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: मैं सभी मैम्बरान से प्रार्थना करती हूँ कि अगर वे इन्ड्रैस्ट ले कर एप्लीकेशन दिलावायें तो हमें खुशी होगी कि लोग इस स्कीम का पूरा लाभ उठा सकेंगे। सब

को कनैव इन मिलने से स्कीम की कामयाबी है और लोग को भी फायदा होता है। अगर कोई इस किस्म के गांव बतायेगे तो हम उनको लोकल एस.ई. और एक्सीयन को कह कर इस स्कीम में शामिल कर लेगे लेकिन यह मैंने पहले ही बताया है कि हम ऐसा एक्सपैरीमेंट करना चाहते हैं। अगर एक्सपैरीमेंट कामयाब रहा तो स्कीम पूरी तरह इम्प्लीमेंट करेगे।

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जहां तक पीने के पानी का ताल्लुक है, हम सारी स्टेट में सारे गांवों में दे नहीं सकते। अगर हम इस तरह से सारी स्टेट में पानी देते हैं तो जितनी हमारी योजना है और सौ गांवों में पानी देने की, वह हम दे नहीं सकते। इस तरह से तो हम चार सौ गांवों को भी नहीं दे पायेगे। अगर हम ऐसा करेगे तो हम डबल कैपेसिटी बनानी पडती है। गांवों में सीवरेज लगाना होगा, पाइप लाईन बिछाने होंगे और सीवरेज नहीं बिछाते हैं तो किचड होगा और मच्छर पैदा होगा जिससे बيمारी फैलती है। इसलिए एक्सपैरीमेंट हम वहा करे जहा नई वाटर सप्लाई स्कीम चालू होनी है। अगर वहा पर लोग एप्लाई कर देगे तो वहा की कैपसिटी के मुताबिक बनायेगे। अब हम गांवों में 10 लिटर पानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से देते हैं। अगर घरों में नलका लागयेगे तो चालीस या पचास लीटर पानी देना होगा। अभी एक माननीय सदस्य ने सवाल भी पूछा कि अगर किसी गांव से पाच सौ एप्लीके इन आ जाती है और पानी की कैपेसिटी थोडी है तो हम कहा से उन्हे पानी देगे। अगर उस गांव

मे हम पानी दे देते है तो साथ के चार और गांव है, उनको दस लीटर के हिसाब से पानी नही दे पायेगे। इसलिए वह एक्सपैरीमेंट उन गावो मे किया जायेगा जहा नयी वाटर सप्लाई स्कीम चालू करनी है। सन 1966 के बाद हमने केवल प्राइवेट कनैक्ट गन्ज दिए है और वे भी उस ग्राउन्डज पर दिये है कि कोई फोजी रिटायर हो कर आया है और उसका बारह मकान पडता है या कोई बीमार आदमी है जो बाहर नही जा सकता या जिसके बिल्कुल साथ ही लाईन पडती है उसे दिए है स्पै ल केस मे दिये है, जनरल देने की कोई बात नही है हमारी योजना है कि आने वाले तीन सालों मे प्रदे 1 मे कोई ऐसा गांव नही रहेगा जहा का पानी खराब हो और वहा पीने का पानी न पहुचा हो, हम ऐसे गावों मे मीठा पानी पहुचाने चाहते है जब ऐसे सभी गांवो मे तीन साल मे पानी पहुचा दिया जायेगा, उसके बाद जो बडें बडे गावं है, वहा घरों मे पानी दिया जायेगा और उसके साथ साथ सीवरेज का भी प्रबन्ध किया जायेगा।

श्री देवी दास: अध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर महोदया ने कहा है कि पांच हजार की जनसख्या वाले या उससे ऊपर की जनसख्या वाले गावों मे पाइप लाईन बिछाई जायेगी। मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या उन छोटे गावो मे पाइप लाईन नही बिछाई जायेगी। जहा पाच हजार से कम आबादी है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: मेरा कहने का मतलब यह है कि छोटे गांव तो उनकी फिरनी से कवर हो जाते है और बडे गावो मे

पाइप लाईन बिछानी पडती है सब जगह पाइप लाईन बिछाते है लेकिन गलियों पक्की न होने के कारण कीचड भी हो जाता है। छोटे गावों से चारो तरफ साथ साथ लाईन बिछा देते है और जो गांव दस हजार या पांच हजार से ऊपर की आबादी के है, उनके अन्दर पाइप लाईन बिछानी पडती है। क्योकि वहां से फासला एक या दो किलोमीटर का हो जाता है।

श्री निहाल सिंह: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने वाटर सप्लाई के बारे मे पालिसी बतायी है। मै उस बारे मे मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि कई जगहो पर छोटे छोटे गावों को मिलाकर स्कीम्ज बनायी गयी है। कहने का मतलब यह है कि 10.12.15 गावों का मिलाकर एक स्कीम बनायी गयी है उसने उनको पाइपड वाटर सप्लाई मिलती है। इसका नतीजा यह होता है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट मे जो टेल के गांव है, उनमे पानी पहुचता ही नहीं है। मेरा कहना यह है कि इस बात की बजाये कि इस स्कीम पर ज्यादा जोर दिया जाये, जिन गांवो मे मीठा पानी अवेलेबल है वहा पर उन गावों को पाइपड वाटर सप्लाई से जोडने की बजाये वहा पर जो कुए है उन पर टैक बगैरा बनारक पब्लिक हैल्थ की तरफ से लोकली पानी सप्लाई किया जाये। मै मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस स्कीम को रिवाईज करके इस बारे मे गौर करेगे कि जहां पर मीठा पानी अवेलेबल है वहा पर टैक बनारक पानी सप्लाई किया जाये?अब यह होता है कि

जो गांव टेल पर है, उन मे एक घटा तो क्या 15 मिनट तक भी पानी नही आता ।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, राव साहब भी भली भाति जानते है कि अभी तक हमने जो वाटर सप्लाई की स्कीम बनायी है यह केवल उन्ही एरियाज के लिए बनायी है जहा पर मीठा पानी अवेलेबल नही था। जहा परनहर का पानी अवेलेबल था यह स्कीम उन एरियाज पर एप्लीकेबल नही है। जहा पर नहर का पानी अवेलेबल नही था। हमने वहा पर वाटर स्पलाई स्कीम बनाकर मीठा पानी सप्लाई करने की कोशिश की है ताकि लोगो तक पानी पहुचाया जा सके। जहा तक मीठा पानी जमीन के नीचे अवेलेबल होने का ताल्लुक है ऐसे एरियाज मे जो बात राव साहब ने कही है ध्यान रखेगे।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जितने टैंक बने हुए है उनकी सफाई की और पूरा ध्यान नही दिया जाता। मेरे हल्के मे फ्लड एफैक्टिड एरिया मे एक गांव थिलौड है। इसमे बरसाता का गन्दा पानी मिक्स हो जाता है क्या मंत्री महोदया इस बात का यकिन दिलायेगी कि एक महीने मे दो महीने मे या तीन महीने मे एक बार टैंक की सफाई अवय हो जाया करेगी ताकि उस पानी मे कोई बीमारी न हो ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, हम सफाई का ध्यान रखते है और सफाई करते रहते है। आनरेबल मैम्बर के

नोटिस मे अगर कोई ऐसी पार्टीकुलर जगह हो जहा पर सफाई न होती तो हम बताये हम सफाई करवा देगे ।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जो बात मुख्यमंत्री महोदय ने बतायी है वह प्रैक्टिकल है । अभी जो आपने स्कीमज फारमुलेट की है वह तो 10 लिटर के हिसाब से बनायी है उन स्कीमज मे पानी इतना अवेलेबल नही है कि आप घरों मे कनैक्शन दे दे । इसलिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह बताना जानना चाहता हू कि जो टर्मज एण्ड कंडिशनज प्राइवेट कौन्सिलर लेने के लिए आपने लेड डाउन कर रखी है(व्यवधान एवम भाोर)

Mr. Speaker: Why not from the Minister?

Chaudhri Surender Singh: Any way, can pass it on to the Minister.(व्यवधान एवम भाोर) वे कडी टर्मज एण्ड कंडिशनज प्राइवेट कौन्सिलर चेज करनी पडगी यह टर्मज एण्ड कंडिशनज प्राइवेट कौन्सिलर ऐसी है जो हरेक आदमी पूरी करेगा और यह कहेगा कि आप उसको प्राइवेट कनैक्शन दो । आपने यह कही नही लिखा है कि घर से दूर कनैक्शन हो इस बात को मधेनजर रखते हुए उसको कनैक्शन मिल जायेगा । अगर हरेक आदमी नान जुडीयल पेपर पर एप्लाइ करेगा तो Government is bound to provide the water connection क्या टर्मज एण्ड कंडिशनज को बदलेगे ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, जैसे मैंने अभी बताया है कि 1966 से लेकर अज तक केवल 58 आदमियों को ही

सारा स्टेट मे प्राईवेट कनैक्टान दिये गये है इनमे भी ज्यादातर विकालांग है या कोई आदमी मिलिट्री मे था । उनके मां बाप बूढ़े है या उनका घर गांव से बाहर है, ऐसे केवल 58 आदमियों को ही कनैक्टान दिया गया है ।

चौधरी फूल चन्द: स्पीकर साहब, ऐसा जवाब कि तीन साल के अन्दर सारे गावों मे पीने के पानी की समस्या को हल कर देगे, स्वागत योग्य जवाब है । मैने पिछले सैठान मे भी यह सवाल उठाया था कि जो सर्वे किया हुआ है उसमे बहुत सारे प्रोब्लम विलेजिज ऐसे है जिनको प्रोब्लम विलेजिज नही दिखाया गया है मंत्री महोदय ने उस समय यह आवासन दिया था कि हम इन गावों का री सर्वे करवा लिया है अगर हा तो उस री सर्वे मे जो प्रोब्लम विलेजिज साबित हुए है उसमे पीने के पानी की व्यवस्था कब तक कर देगे?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, हमने दोबारा सर्वे करवा लिया है और केस भारत सरकार को भेजा हुआ है । हमे उम्मीद है कि भारत सरकार की तरफ से हमे उन एडीटानल प्रोब्लम विलेजिज के लिए मदद मिलेगी । अभी वहां से केस वापिस आया नही है हमे पूरा उम्मीद है क्योकि भारत सरकार और हरियाणा सरकार दोनो ही पूरी तरह से इसके लिए चिन्तित है ।

श्री अध्यक्ष: मैडम, बात ऐसे है कि हमारे यहां कुछ जगह ऐसी है जहां पर पानी तो मीठा है लेकिन वहा पर अगर

नलका लगाये तो 6 महीने में ही उसकी पाई खत्म हो जाती है। आपको यह भी पता है कि एक नलका लगाने में 4-5 हजार रुपये लग जाते हैं आम आदमी की इतनी कैपसिटी नहीं होती कि वह साल में दोबारा नलका लगावा सके। इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, सारी स्टेट में बहुत थोड़ा एरिया ऐसा है जैसा आपने बताया है।

श्री अध्यक्ष: भाहबाद हल्के में कम से कम 50 गांव ऐसे हैं जहां पर यह दिक्कत है।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, आपकी बात ठीक है करनाल और कुरुक्षेत्र में कुछ एरिया ऐसा है जहां पर नीचे का पानी मीठा है। जहां तक इन एरियाज के लिए कुछ करने की बात का ताल्लुक है उसके लिए मैं यह बताना चाहती हू कि तीन प्रायरिटीज बनी हुई है। सबसे पहले तो प्रोब्लम विलेजिज को लेगे फिर एडी अनल प्रोब्लम विलेजिज को लेगे और उसके बाद हम नान प्रोब्लम विलेजिज को लेगे हमारी यह कोर्चि है कि हम जल्दी से जल्दी हर गांव में मीठे पानी उपलब्ध करवाये। पिछले साल में हमने 810 गांव कवर किये हैं और इस साल 506 गांव रखे हैं, हमें यह उम्मीद है कि इस योजना के अन्त तक हम सब को मीठा पानी उपलब्ध करवा पायेगे।

श्री अध्यक्ष: जितनी भी आपके टैप गावो मे लगे हुए है वे इन्फ्रूि गयल आदमियों के घरों के नजदीक लगे हुए है वे टैप्स बैकवर्ड और हरिजन बस्तियों पानी नहीं देते। हर जगह यह बड़ी भारी कम्प्लेंट है।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: इस संबध मे मैने पिछले महीने अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी। उसमे मैने यह आदे ा दिये थे कि हरेक गांव मे यह देखे कि जा पर हरिजन बस्तिया मे प्वायटस नहीं लगे हए, वहा तुरन्त लगाये जाये। अगर हो सके तो पचायत से कोआप्रे ान लेकर वहा पर छोटा टैक भी बना दे। कहने का मतलब यह है कि हम हरिजन बस्तियो के लिये पानी का इन्तजाम कर रहे है। हमारी सरकार इस बारे मे पूरी तरह से सीरियस है।

श्री एस.सी. चौधरी: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने बड़ी ही वाजिब बता कही है कि यह फिजीबल नहीं होगा कि हर जगह पर प्राइवेट कनेक् ान दिये जाये। कई ऐसी जगहे है जहा पर स्कीम तो 10 लिटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से बना रखी है लेकिन गावों मे 10 लिटर के हिसाब से पानी पहुंचता ही नहीं है। कई सालो की एक स्कीम बनी पडी है जिसका ना सीकरी स्कीम है। पिछले साल भी मेरे सवाल के जवाब मे सरकार ने यह कहा था कि वहा पर बहुत जल्दी ही एक बूस्टर लगा दिया जायेगा। मै यह जानना चाहता हू कि इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि आजकल स्टेट मे इडट्रेलाईजे ान बड़ी

तेजी से हो रही है, हर देहात का भाई चाहे वह सैमी अर्बन या विलेजिज मे रह रहा है, वह चाहता है कि वह भी भाहर के बराबर की सहूलियते हासिल कर सके, उस सीकरी स्कीम को जो कि 10 लिटर के हिसाब से बनायी गयी थी, उसको पूरी तरह से कामयाब किया जायेगा क्या इस बारे मे मंत्री महोदया कोई वाजिब जवाब देगी ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, मेरे नोटिस मे तो ऐसी स्पैसिफिक बात कोई नही है कि कोई स्कीम पूर हो और वह 10 लिटर पानी भी नही दे पाती हो । इस बात के लिये सरकार आलरेडी काम कर रही है जैसे कोई 10 गावों की एक ग्रिड है वहा पर टेल के गावें तक पानी पहुचाने के लिए हमने जनरेटर लगाने के आर्डर भी दिय हुये है। अगर कोई स्पैसिफिक गांव की बात इनके नोटिस मे हो तो वह हमे बतायें, हम जरूरत के मुताबिक इंतजाम करने की पूरी कोशिश करेगे।

श्री एस.सी. चौधरी: स्पीकर साहब, मेरा सीधा सा प्र न है वाटर सप्लाई स्कीम जो बल्लभगढ सब डिवीजन से होकर फरीदाबाद के गावों की कवर करती है, वहा रिजर्वायर बनाने की बता थी। पिछले साल भी वह वायदा किया गया था कि वहा पर बूस्टर लगाकर रिजर्वायर मे पानी रखने का इन्तजाम किया जायेगा, क्योकि वहा पर कई इलाके ऐसे है जहा पानी पहुचाते ही नही है। मै यह पूछना चाहता हू कि सीकरी की स्कीम मे इतनी डिले क्यो की जा रही है। क्या इस काम को जल्दी से पूरा कराया जायेगा ?

यह स्कीम हुई पडी है 13 लाख रूपये का एस्टीमैट भी पास हुआ पडा है ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: असल मे क्वै चन तो प्राइवेट कनैव गन्ज का था। अब इस समय मेरे पास हरेक गांव की स्कीम का तो रिकार्ड नही है, मै आदरणीय मैम्बर को बाद मे पता करके अव य बता दूंगी।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, मै आपका द्वारा सरकार के नोटिस मे लाना चाहता हू कि हरियाणा मे वाटर सप्लाई का प्रोगाम एक डिकेड से चल रहा है लेकिन जिन गावों मे वाटर सप्लाई का काम पूरा हो चुका है वहा उनकी मेटीनेस का कोई इत्जाम सरकार की और से नही हैं मिनिस्टर महोदया ने अभी कहा है कि अगर कही कोई कमी है तो वह सरकार के नोटिस मे लाए उस कमी को दूर किया जाएगा । स्पीकर साहब मोरनी मे वाटर सप्लाई की स्कीम पर 1.10 करोड रूपया खर्च किया जा चुका है और अगर पांच चार लाख रूपया और खर्च कर दिया जाए तो उस वाटर सप्लाई से पन्द्रह हजार आदमी फायदा उठा सकते है। पांच चार लाख रूपये खर्च न करने की वजह से पिछले दो साल से यह स्कीम बेकार पडी हुई है क्या मुंख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि किन वजुहात से वह स्कीम पूरी नही हो रही है, क्या उन आफिसर्ज के खिलाफ कार्यवाही करेगे जिन्होने सरकार का एक करोड से भी ज्यादा रूपया खराब कर दिया है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने अभी बताया है कि उस स्कीम पर एक करोड रूपये से भी ज्यादा सरकार का खर्च हो चुका है और पांच सात लाख रूपए की वजह से वह स्कीम अधुरी पडी है और लोगो को पानी नही पहुचा है । माननीय से पहले इस बात का जिक्र नही किया आज ही बताया है.

.....

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, मैने पिछले सै ।न मे जिक्र किया था ।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब अगर उस स्कीम पर एक करोड से ऊपर रूपया खर्च हो चुका है और सिर्फ पांच सात लाख की बात है तो अगले सै ।न तक यानी छ महीने के अन्दर उसको पूरा कर देगे । स्पीकर साहब, अगर बीस लाख रूपए खर्च करके भी वह स्कीम पूरी होती है तो हम उसको अगले छ महीने मे पूरा कर देगे ।

स्पीकर साहब, दूसरी बात श्री एस.सी. चौधरी ने कही कि उनके यंहा कोई वाटर सप्लाई की स्कीम तेहर लाख की है, वह पूरी नही हुई है । मै सदन मे बताना चाहता हू कि हम तेरह लाख रूपया देकर छ महीने के अन्दर उस स्कीम को पूर कर देगे ।

अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि गरीब आदमियों के मोहल्लो मे पानी की टूटी नही है, बडे बडे आदमी अपने घरों के सामने टूटी लगवा लेते है जिससे गरीब आदमियों को पानी नही

मिलता । अध्यक्ष महोदय हमने बाकायद सारी स्टेट मे हिदायत और सर्कुलर जारी किए हुए है कि जहा कही बीस पच्चीस घरों का मोहल्ला है वहा पर एक टूटी लगनी चाहिए। आपकी बात के बारे मे चैक करवा लेगे और जंहा कही टूटी नहीं है वहा हर हालत मे छ महीने के अन्दर काम पूरा करवा दिया जाएगा। अगर कोई हिदायत या कमी रह जाती है तो मैं माननीय सदस्यों मे प्रार्थना करुंगा कि वे सरकार को नोटिस मे लाए।

श्री अध्यक्ष: मैं आप के नोटिस मे एक बात लाना चाहता हू कुछ भाहरों मे यह हालत है कि जो इफिलूरे इन आदमी है वे नीचे से पम्प लगाकर ऊपर टै कमे पानी भर लेते है और उनके यहा सारा दिन पानी चलता रहता है इस वजह से जो दूसरे गरीब आदमी मोहल्लो मे रहते है उनको पानी नहीं मिलता। इन लोगों के खिलाफ अफसरान भी कोई ऐक इन नहीं लेते या तो वे डरते है या कुछ और खास बात है।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, हो सकता है कुछ घरों मे ऐसा होगा हम चैक करवा लेगे । कुछ लोग मीटर फिट करवा कर पम्प मे अपने टैक मे पानी डलवा लेते है और उसका यूज करते है और दूसरे पानी का भी यूज करते रहते है जो आपने का है उसकी हम चैकिंग करवाएगे।

Loss Suffered by Haryana Dairy Development Corporation

***1030 Shri Ram Bilas Sharam:** Will the Minister of State for Dairy Development be pleased to State-

(a) whether any decision for the winding up of Haryana Dairy Development Corporation has been taken; and

(b) if so, the date of the said decision together with the time by which the decision referred to above is likely to be implemented>

डेरी विकास राज्य मंत्री (श्री जसवत सिंह चौहान):

(क) नहीं जी

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री राम बिलास भार्मा: क्या मंत्री महोदय बताने का कृपा करेगे कि हरियाणा डेरी डिवेलपमेंट कार्पोरे इन इस समय कितने घाटे में या मुनाफे में चल रही है? स्पीकर साहब, एक बार ऐस्टीमेंट कमेटी ने एक सर्वे किया था। जो कोआप्रे इन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है, उन्होंने बताया था कि डेरी डिवेलपमेंट कार्पोरे इन लगातार लाखों रूपए के घाटे में जा रही है और इसको वाइड अप करने जा रहे हैं वाइड अप इसलिए नहीं किया जा रहा है कि इसका ऑडिट नहीं हुआ है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि इसको कब वाइड अप किया जाएगा?

श्री जसवन्त सिंह चौहान: स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि हमारे एम.एल.ए. साहब को डेरी विकास निगम के बारे में पता ही नहीं है। वे कौन सी बात पूछ रहे हैं यह वे जानते ही

नही। स्पीकर साहब, डेरी विकास निगम ने अपने प्लाअ और प्रोपर्टी को जा उसकी लिखित कीमत थी उसको दस फीसदी लीज पर फ़ैडरे इन को दिया हुआ है। जो निगम का स्टाफ था उसको भी इस फ़ैडरे इन को सौप दिया है। एम.डी. फ़ैडरे इन और निगम दोनों का काम करता है। अध्यक्ष महोदय कार्पोरे इन ने कई जगहो से कर्जा लिया हुआ है उसको फ़ैडरे इन में तबदील करने की मन्जूरी ले रहे है। ज्यों ज्यो मन्जूरी मिल जाएगी त्यो त्यों हम उसको फ़ैडरे इन में तबदील करते जायेगे। बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज ने फ़ैसला लिया है कि कार्पोरे इन का जो नफा नुकसान है वह फ़ैडरे इन को दिया जाएगा।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय जी ने यह बताया है कि कार्पोरे इन तो नहीं चल रही है फ़ैडरे इन चल रही है। डेरी डिवेलपमेंट कार्पोरे इन बन्द हो गई है फ़ैडरे इन इज रनिंग और कार्पोरे इन के प्लांट और मीनिरी का पट्टा फ़ैडरे इन को दे दिया है अध्यक्ष महोदय, फ़ैडरे इन में सारा स्टाफ कार्पोरे इन का है और दोनों का एडमिनिस्ट्रे इन एक है सिर्फ नाम ही चेन्जड है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि क्या कारण थे जिनकी वजह से कार्पोरे इन को फ़ैडरे इन में तबदील किया गया था ?

श्री जसवन्त सिंह चौहान: स्पीकर साहब, अभी मैंने बताया है कि निगम को फ़ैडरे इन को दे दिया है। स्पीकर साहब, नुकसान का कारण यह था कि हमने तीन ऐजन्सियों से एक तो

सरकार ने दूसरे बैक्स से और तीसरे इंडियन डेरी कार्पोरे इन से कर्जा लिया हुआ था। हम उस पैसे का ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं और हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा था इस विषय को फ़ैडरैन को पट्टे पर दे दिया गया है इस वजह से कार्पोरे इन को फ़ैडरे इन में बदलना पड़ा है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा डेरी विकास निगम को 1977 में 35 लाख रुपये सालाना के हिसाब से फ़ैडरे इन को लीज पर दिया गया था। क्योंकि निगम को चलाने के लिये बहुत सी सस्थाओं पैसा नहीं देती थी, इसलिये इस निगम को लीज पर फ़ैडरे इन को देना पड़ा था। अब 35 लाख रुपया सालाना फ़ैडरे इन कार्पोरे इन को देती है। जहां तक इसके नफे और नुकसान का सवाल है, तकर्रीबन 31 लाख रुपया सालाना नुकसान भी हो जाता है। मिल्क प्लांट का मकसद प्रोफिट कमाना नहीं है। किसानों की सुविधा देने के लिये, किसानों का दूध ठीक भाव पर बिक जाए, किसानों की हालत ठीक रहे और किसी तरह की किसानों की दिक्कत न हो, इन सभी बातों को देखने के लिये यह सस्था काम कर रही है इसलिए इन सभी बातों को देखते हुए इसमें घाटा भी हो सकता है लेकिन इस घाटे का घाटा नहीं मानना चाहिये। अध्यक्ष महोदय आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हरियाणा के अन्दर सभी भूगर मिल्ज घाटे में चल रही है लेकिन सरकार ने किसानों के हितों को हर लिहाज से सामने रखा है। किसानों के गन्ने का भाव उनको सही देना पड़ता है, इसलिए सभी

भुगर मिलज घाटे मे चल रही है। अत इसमे घाटे वाली ऐसी कोई बात नहीं है। केवल 31 लाख रूपया सालाना का घाटा हैं। मै यहां हाउस मे यह भी बता देना चाहता हू कि अभी इस निगम को बन्द करने का सरकार का कोई ऐसा विचार नहीं है। सिर्फ फ़ैडरे इन को हमने लीज पर दिया हुआ है। अगर फ़ैडरे इन का काम ठीक चलता रहेगा तो ठीक है। अगर फ़ैडरे इन का काम सही नहीं होगा तो इसको वापिस निगम के पास भी लिया जा सकता है।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री महोदय जी ने बताया कि ये फ़ैडरे इन किसानों की भलाई के लिये, किसानों की सुविधा के लिये काम कर रही है। क्या वे बताएंगे कि किसानों कि फ़ैडरे इन की तरफ दूध का कितना पैसा बकाया है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय हमने एक फ़ैसला किया है कि हर हफते दूध की पेमेंट किसानो को होनी चाहिये। हम हर हफते दूध की पैमट किसानो को करते भी है। अगर माननीय सदस्य के नोटिस मे कोई बात हो कि फला जगह पर दूध का पैसा किसानों को नहीं दिया गया है। तो वे हमारे नोटिस मे लांए हम हर हालत मे दूध की कीमत अदा करवाएं।

Opening of Schools in Sector 22 end 23 of Faridabad

***1030 Shrimati Sharda Rani:** Will the Minister of State for Education be pleased to State-

(a) whether it is a fact that school buildings have not been constructed in any of the colonies set up by the Housing Board in the State and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the school buildings in all the above said colonies particularly in Sector 22 and 23 of Faridabad?

Minister of State for Education Shri Jagdish Nehru:

(a) School buildings have not been constructed by the Housing Board for the Education Department in such colonies for exclusive use of Housing Board Colonies.

(b) There is no proposal under consideration with the Education Department for constructing school buildings in Housing Board colonies. However a Government Branch of Primary School is running in sector 22 Housing Board Colony Faridabad in a building provided by the Water Association.

श्रीमती भादरा रानी: अध्यक्ष महोदय मेरा यह सवाल शिक्षा एवम हाउसिंग बोर्ड से सम्बन्धित है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि ऐजुकेशन विभाग का स्कूल बिल्डिंग बनाने का कोई इरादा है ? क्या सरकार की कोई ऐसी पालिसी है जिसके तहत हाउसिंग बोर्ड के अन्दर जो लोग रहते हैं उन्हें भी शिक्षा दी जाए या उन्हें अशिक्षित रखने का ही सरकार का इरादा है ? वे बहुत ही कमजारे लोग होते हैं। 20 सालों में तो वे अपने छोटे छोटे मकानों की किंमतें ही दे पाते हैं। अगर वे अपने जुगाड से

स्कूल की अपनी बिलडिंग बनाते भी है तो आप सोचगे कि कितने दिनों मे वे चन्दे का पैसा जमा करेगे जिससे ऐडीक्वेट स्कूल की बिलडिंग बन सकेगी। जब तक वे ऐसा नहीं कर पाते है तब तक क्या वहा के लोगो को अि शिक्षित रखने का इरादा है?

श्री जगदी । नेहरा: अध्यक्ष महोदय, लोगो को अि शिक्षित रखने की ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के अन्दर ि शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन अब जो नये प्लान हाउसिंग बोर्ड के बने है, उनम यह प्रावधान किया गया है जैसा कि भिवानी और फरीदाबाद वगैरहा मे है। जंहा तक फरीदाबाद के सैक्टर 22 और 23 का सवाल है, वहा आलरेडी एक प्राईमरी स्कूल चल रहा है। इसके साथ मे एक किलोमीटर की दूरी पर सारन नामक गांव है वहां भी प्राईमरी स्कूल है इसके इलावा 6 अन रिक्गनाईजड स्कूल भी चल रहे है। ि शिक्षा की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वहां पर कोई स्कूल न हो या एक किलोमीटर से दूर बच्चो को जाना पडता हो।

श्रीमती भारदा रानी: सर, आप जानते है कि जो दूसरे स्कूलज होते हे वे तो एक तरह की भाप्स ही होते है। इनम ज्यादातर लोग अपने बच्चो को नहीं भेजते जहां तक गावों का सवाल है जैसा कि इन्होने बताया है आप जानते है फरीदाबाद कम्पलैक्स के गावों की पापूले िन बाहर से आये हुए लोगो के कारण बहुत ज्यादा बढ गयी है। उनके पास अपना ही बिलडिंगज इन ऐडीक्वेट है। इस बारे मे मंत्री जी पता भी करवा ले कि उस

गांव को अपनी बिलडिंगज कितनी इन एडीकवेट है इस स्कूल को दूसरी जगह बनाने की आव यकता है इन्होंने यह भी कहा है कि कुछ नहीं कालोनीज है जो भिवानी और हिसार वगैरह में बना रहे है लेकिन जो पुरानी कालोनीज है क्या उनमें भी सरकार कोई ऐसा प्रावधान कर रही है जो कालोनीज आलरेडी बनी हुई है क्या उसमें शिक्षा देने और स्कूल बिलडिंगज बनाने के लिए सरकार कोई प्रावधान कर रही है। साथ में मंत्री महोदय ने कहा कि सैक्टर 22 में एक स्कूल शिक्षा विभाग ने चलाया हुआ है इसमें हमें कोई सन्देह नहीं है लेकिन यह बिलडिंग इन एडीकवेट है क्या वहां पर सरकार का कोई नयी बिलडिंग बनाने का विचार है ? पहली बिलडिंग भी इन्हे खाली करनी पड रही है वे अब तीन वगैरहा डाल कर किसी तरह से अपना जुगाड कर रहे है लेकिन वह जुगाड भी नहीं हो पा रहा है। जैसे सैक्टर 23 है, उस जगह पर बिलडिंग का प्रावधान करने की आव यकता है। क्या सरकार इस तरफ ध्यान देगी ?

श्री जगदी ा नेहरू: अध्यक्ष महोदय जो कालोनी पहले की बनी हुई है उनमें यह प्रावधान नहीं था। अब यदि एक किलोमीटर से दूर जाना पडेगा तो जहा ये कहेगे हम प्रावधान कर देगे और स्कूल खोल देगे। जंहा तक दूसरी स्थिति का ताल्लुक है हाउसिंग कालोनी जो अब सोनीपत में, फेज 1 और 2 में, वीयर्ज कालोनी पानीपत में, नूह में अम्बाला कैट में बन रही है, उन में यह प्रावधान किया है हाउसिंग बोर्ड की छोटी कालोनीज में स्कूल का

प्रावधान इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पर आलरेडी नजदीक में स्कूल चल रहे हैं जैसे सैक्टर 22 में एक प्राइमरी स्कूल नजदीक ही चल रहा है। और 6 अनरिकग्नाइज्ड स्कूल और भी चल रहे हैं जहां पर आवयकता होती है वहां पर यह प्रवाधान किया जाता है लेकिन जहां आवयकता नहीं होती वहां स्कूल नहीं खोला जाता।

श्री ए.सी. चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत शिक्षा मंत्री महोदय की तवब्जो दिलाना चाहता हू कि सैक्टर 22 जिसका ये जिकर कर रहे हैं वहां के कुछ लोगो ने चन्दा इकटठा करके और वहां के लोकल कम्पलैक्स ने पैसा देकर के पार्क में छोटे छोटे बनाए हुए हैं जिनकी छते बहुत टपकती है वह कालोनी बहुत बडी है अगर वहां हायर सैकण्डरी स्कूल भी खोला जाए तो भायद वह स्कूल भी सौफाइस नहीं होगा। उसके साथ ही सैक्टर 22 और 23 के पीछे 10 हजार झुग्गिया हैं जहां कोई स्कूल नहीं है जो स्कूल है उसमें बच्चे इसलिए दाखिला नहीं ले पाते क्यो कि उसमें केवल 4 ही कमरे हैं और वे भी हटस में हैं। जगह बहुत कम है। मैं यह समझता हू कि सरकार का यह कहना उचित नहीं है कि वहां पर स्कूल नहीं बनाया जा सकता। जब पार्क में आलरेडी जगह है और स्कूल छोटे स्तर पर चल भी रहा है तो सरकार को झुग्गी झोपडी वालो की तरफ और खास तोर पर कालोनी वालो की तरफ ध्यान देने की आवयकता है वरना बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे। जहां तक सारन स्कूल का ताल्लुक है सारन स्कूल तो अपने बच्चो को ही पूरा दाखिला नहीं दे पाता जब कि

70 हजार की आबादी को पजाबी कालोनी और जवाहर कालोनी के साथ के एरिया के बच्चे 3-3 किलोमीटर की दूरी से आते जाते हैं मैं चाहता हू कि सरकार इस मामले में कैटेगरीकली अभ्योरैस दे जंहा एक एक लाख की आबादी है वह 3 किलोमीटर दूरी से बच्चे क्यों जाएं अगर बच्चे पढ़ने के लिए दूर न जा पाएंगे तो इससे दे 1 का अहित होगा। इसके लिए सरकार को हर तरफ की प्रोटैक्शन देनी चाहिये।

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय सरकार ने एक फैसला किया है हुडडा भी कालोनी बनाता है और हाउसिंग बोर्ड भी कालोनी बनाता है 100 या 100 एकड़ से ज्यादा जमीन एक्वायर करके जहा हुडा या हाउसिंग बोर्ड कालोनी बनाता है वहा पर स्कूल बनाने का प्रावधान एक छोटा हस्पताल और डिसपैन्सरी बनाने का प्रावधान रखा जाता है प्ले ग्राउंड की जगह भी वाफायदा रखी जाती है जैसा कि ए.सी. चौधरी साहब ने बताया कि जंहा पर पुरानी कालोनी बनी हुई है वहा लोगो की कठिनाईयो हो सकती है क्योंकि बेसिक स्कीम में जगह नहीं रखी गई थी इसके अलवा बहुत सी जगहो पर अनअथोराइज्ड कालोनीज बनी हुई है जिनका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब बन गयी है तो सरकार का यह कर्तव्य बन जाता है कि वहां लोगो को पानी की सुविधा सीवरेज की सुविधा, बिजली की सुविधा, हस्पताल की सुविधा, स्कूल की सुविधा, दी जाए। इस बात को हम पूरा

ध्यान में रखेंगे। जैसा इन्होंने बताया कि वहाँ यह कठिनाई है, सरकार उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेगी।

चौधरी फूल चन्द: क्या मंत्री जी बताएँगे कि हरियाणा के हर गाँव में प्राइमरी स्कूल खोल दिया गया है और क्या सरकार की यह नीति है कि जिन गाँवों की पंचायतें स्कूल की बिल्डिंग्स मेंटेन नहीं कर सकती उनको मेंटेन करने का सरकार प्रावधान करेगी?

श्री जगदीश नेहरू: हरियाणा के सारे गाँवों में प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ स्कूल न हो। यहाँ तक कि ढाणियों में भी जहाँ 30-40 बच्चे होते हैं, वहाँ भी स्कूल खोले गये हैं जो कि तीसरी क्लास तक के होते हैं जहाँ तक स्कूलों की बिल्डिंग्स को मेंटेन करने की बात है, केवल हाई स्कूल की पी.डबल्यू.डी. को दिए जाते हैं, वह भी तब अगर पंचायत यह रैजोल्यूशन पास कर दे कि इस स्कूल की सारी लायबिलिटी बगैरह हम सरकार को देते हैं। प्राइमरी और मिडल स्कूलों को मैचिंग ग्रांट, आर.एल.जी.पी. और एन.आर.ई.पी. स्कीमों के तहत ठीक किया जाता है।

बहिन भान्ति देवी: स्पीकर साहब, गाँवों में तो पंचायतें स्कूलों के लिए जमीन बगैरह दे देती हैं लेकिन आप जानते हैं कि बाहरों में स्कूलों के लिए कोई भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं होते इसलिए वहाँ पर स्कूलों के भवन नहीं हैं। बाहरों में पार्टीशन

के बाद किराए बिल्डिंग में स्कूल बने थे या तो वे टूट गए हैं और या मालिक मकान ने अपनी जगह खाली करवा ली है। करनाल भाहर के बारे में मुझे मालूम है वहां पर प्राइमरी एजूके इन सरकार के हाथ से निकलती जा रही है प्राइवेट घरेलू स्कूल बढ़ते जा रहे हैं वहां पर केवल राजकीय प्राइमरी स्कूल का अपना भवन है जिसके क्लासे लगती थी, अब एक दो स्कूल जो खाली करवा लिए हैं उनके बच्चे भी इसी स्कूल में आ गए हैं उसके लिए अब थोड़ी सी मदद मिली है। उस स्कूल में अब चार पांच कमरे और बनेंगे। वहां पर एक हाई स्कूल की भी जरूरत है क्योंकि आस पास कोई हाई स्कूल नहीं है एक मिडिल स्कूल था वह भी खाली करवा लिया। इसलिये भाहरो में भी ऐसी योजना बनाई जाए ताकि वहां भी प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों के भवन बनाए जाए। इसी तरह से प्रेम नगर में एक हाई स्कूल है यह स्कूल 38 साल पहले बना था जो कि हट टाईप था उसकी छतें टपकती हैं इसलिए भाहरो में स्कूल भवन निर्माण का काम सरकार अपने हाथ में ले ले तभी अनिवार्य शिक्षा का प्रोग्राम चल पाएगा। गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नि लुक शिक्षा द्वारा लाभान्वित हो सकेंगे।

श्री जगदी । नेहरू: स्पीकर साहब, बहिन जी ने ठीक कहा कि भाहरो में भी स्कूलों की हालत खराब है। उसका कारण यह है कि गावों में कम्युनिटी एजूके इन थी चन्दा इकट्ठा कर लिया लेकिन भाहरो में 1947 के बाद कम्युनिटी का सिस्टम नहीं रहा, स्कूलों की हालत खराब रही। जो वक्फ बोर्ड या

रिहैबलीटे ान की जमीन थी अब उसकी हम एक्वीजि ान कर रहे है इस साल काफी भाहरो मे सुधार करने की कोि ा ा कर रहे है ।

Mr. Speaker: Question Hour is over

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तांराकित प्र नो के लिखित उत्तर

Fixation of number of hour for the supply of electricity

***1308 Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Minister for irrigation & Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to fix the number of hours for which electricity is to be supplied to Domestic. Industrial and Agricultural consumers in the State, if so, the details thereof?

Irrigation and power Minister(Charudhri Shamsher Singh Surjewala): The proposal to fix number of hours for supply of electricity to domestic, industrial and agricultural consumers in the State will not be practicable as the same depends upon variation in availability and demand of power on day to day basis. Under the regulatory measures being followed the supply to various categories of consumers has generally been as follows in recent months:-

(i)	Agriculture	6 to 10 hours a
-----	-------------	-----------------

		day.
(ii)	Industry	6 to 8 hours a day (one or two weekly off days)
(iii)	Domestic Urban Rural	15 to 19 hours a day 12 to 16 hours a day

From 17th September however all restrictions have been removed.

Pharmacy diploma institutions in the State

***1045. Chaudhri Kulbir Singh Malik:** Will the Minister of State for Health be pleased to state

(a) the number of Pharmacy Diploma institutions existing in the State at present;

(b) the name of sanctioning authority for the opening of the institutions referred to in part together with the criteria adopted for according the sanction therefor and

(c) whether the qualifying candidates are required to do apprenticeship before the said Diploma is awarded to them ?

परिवहन राज्य मंत्री चौधरी चन्दा सिंह:

(क) सात

(ख) कोर्स आरम्भ करने हेतू फार्मैसी कौंसिल आफ इण्डिया की अनुमती प्राप्त होने के बाद हरियाणा राज्य सरकार

(ग) जी हा।

Government college for women

***1000. Dr Bhim Singh Dahiya:** Will the Minister of State for Education be pleased to State-

(a) the names of Govt. College for women opened Not conerted during the period from November 1966 to date;

(b) the number of students enrolled at each of the existing Govt. College for Women during the year 1984-95 toghether with the number of seats available at each of the hostels, if any, attached to these colleges: and

(c) whether 10+2 system of Education has been introduced in the Sated if so the names of such Govt. Girls High Schools as have been selected for the purposed to date?

शिक्षा राज्य मंत्री श्री जगदीश प्रसाद नेहरा:

(क) भून्य।

(ख) कालिज का नाम	छात्र सख्या	महाविधालयो के साथ सलगन छात्रावासो मे उपलब्ध स्थान
(1) राजकीय महिला	1935	94

महाविधालय रोहतक		
(2) राजकीय महिला महाविधालय गुडगावं	2035	80

(ग) जी हा 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली राज्य मे लागू कर दी गई है परन्तु कोई भी राजकीय कन्या उच्च विधालय इस प्रणाली हेतू नही चुना गया है।

अताराकित प्र न एवम उत्तर

Special Grants to Municipal Committess

200. Shri Fateh Chand Vij: Will the Minister of State for Local Government be pleased to State wherher any special grants have been given to the Municiplities during the year 1984-85 if so, the names of such Municiplities together with the amount of grant given to them speartely ?

Minister of State for Local Government, Shri Om Parkash Mahajan:

(i) Yes.

(II) As indicated in Annexure 'A' to 'J'

ANNEXURE A

1. For Revenue Earning Schemes:

Sr.No	Name of M.C	Amount of grant
1.	Fatehbad	0.33
2.	Gohans	0.35
3.	Kalayath	0.35
4.	Hassanpur	0.35
5.	Nuh	0.35
6.	Uchana	0.35
7.	Narwana	0.35
8.	Bahadurgarh	0.35
9.	Safidon	0.35
10.	Chhachharuli	0.30
11.	Jakhal	0.35
12.	Julana	0.35
13.	Ladwa	0.35
14.	Samalkha	0.35
15.	Tosham	0.35
16.	Kalanapur	0.35
17.	Sadhaura	0.35
18.	Bawal	0.35

19.	Gharaunda	0.35
20.	Assandh	0.35
21.	Ganaur	0.35
22.	Kalka	0.35
23.	Jagadhi	0.35
24.	Palwal	0.35
25.	Tohana	0.35
26.	Mandi Dabwali	0.35
27.	Shahbad	0.35
28.	Bawanikhera	0.35
29.	Pundri	0.35
30.	Radaur	0.35
31.	Radaur	0.35
32.	Ateli Mandi	0.35
33.	Pehowa	0.35
34.	Cheeka	0.35
	Total	12.00

ANNEXURE B

II. For Development

Sr.No	Name of M.C	Amount of grant
1.	Palwal	0.50
2.	Ambala City	0.70
3.	Jagadhri	0.50
4.	Kalka	0.50
5.	Kharkhoda	0.38
6.	Jind	1.00
7.	Faridabad	---
8.	Ambala Sadar	0.70
9.	Bhiwani	0.70
10.	Gurgoan	0.70
11.	Hissar	0.70
12.	Hansi	0.70
13.	Karnal	0.70
14.	Kaithal	1.00
15.	Panipat	0.70
16.	Rohtak	0.70
17.	Rewari	1.00
18.	Thanesar	0.70

19.	Sonepat	0.70
20.	Sirsa	1.00
21.	Yamunanagar	0.70
22.	Bahadurgarh	1.00
23.	Charkhi Dadri	0.50
24.	Fetehtbad	0.50
25.	Gohana	0.50
26.	Jhajjar	1.00
27.	Mandi Dabwali	0.50
28.	Narnaul	0.50
29.	Narwana	2.00
30.	Shahbad	0.55
31.	Tohana	0.50
32.	Kalayat	0.51
33.	Bawal	1.00
34.	Hodel	0.50
35.	Nilokheri	1.00
36.	Traori	1.00
37.	Pundri	1.00

38.	Gharauda	1.00
39.	Julana	1.00
40.	Pehowa	2.88
41.	Cheeka	1.00
42.	Radaur	1.00
43.	Uchana	1.00
44.	Kalanaur	0.50
45.	Ateli Mandi	0.38
46.	Kanina	0.38
47.	Loharu	0.38
48.	Tohham	0.38
49.	Uklana Mandi	0.38
50.	Hathin	0.38
51.	Hassanpur	0.38
52.	Toaru	0.38
53.	Ferojpur Jhirka	0.38
54.	Rania	0.38
55.	Brara	0.38
56.	Buria	0.38

57.	Chhacharuli	0.38
58.	Naraingarh	0.38
59.	Indri	0.38
60.	Beri	0.38
61.	Raipur Rani	0.38
62.	Ganaur	0.38
63.	Mahindergarh	0.38
64.	Bwani Khera	1.00
65.	Safidon	0.38
66.	Nuh	0.38
67.	Nagina	0.38
68.	Haily Mandi	0.38
69.	Pataudi	0.38
70.	Feruq Nagar	0.38
71.	Kalanwali	0.38
72.	Ladwa	0.38
73.	Sadhaura	0.38
74.	Shahzadpur	0.38
75.	Assandha	0.38

76.	Sohna	0.38
77.	Samalkha	0.38
78.	Mehm	0.38
79.	Ratia	0.38
80.	Ellenabad	0.38
81	Jakhal	0.38
	Grand Total	50.00

ANNEXURE 'C'

III. For the Civic Amenities Development

Sr.No	Name of M.C	Amount of grant
		Rs. In Lacs
1.	Sonepat	10 ,,
2.	Gohana	3 ,,
3.	Ganaur	2 ,,
4.	Kharkhauda	2 ,,
5.	Bahadurgarh	8 ,,
6.	Safidon	5 ,,
7.	Julana	3 ,,
	Total	33 Lacs

ANNEXURE 'D'

IV For environmental Improvemen of Urbans Stums:

Sr.No	Name of M.C	Amount of grant Rs. In Lacs
1.	Sonipat	1.75
2.	Jind	1.75
3.	Thanesar	1.75
4.	Kaithal	1.75
5.	Ambala City	1.75
6.	Panipat	1.75
7.	Rewari	2.75
8.	Bhiwani	2.75
9.	Hansi	2.75
10.	Gurgaon	2.75
11.	Sirsa	2.75
12.	Ambala City	2.75
13.	Yamyna Nagar	2.75
14.	Karnal	2.75
15.	Rohtak	2.75

16.	Hissar	4.75
17.	Gohana	1.50
18.	Narnaul	1.50
19.	Narwana	1.50
20.	Palwal	1.50
21.	Mandi Dabwali	1.50
22.	Shahbad	1.50
23.	Kalka	1.50
24.	Jagadhri	1.50
25.	Charkhi Dadri	1.50
26.	Tohana	1.50
27.	Fatehbad	1.50
28.	Bahadurgarh	1.50
29.	Jhajjar	3.00
30.	Ateli Mandi	0.35
31.	Bawal	0.35
32.	Kanian	0.35
33.	Loharu	0.35
34.	Tosham	0.35

35.	Uklana Mandi	0.35
36.	Jakhal	0.35
37.	Uchana	0.35
38.	Kalayath	0.35
39.	Hathin	0.35
40.	Hassan Pur	0.35
41.	Taoru	0.35
42.	Ferozepur Jhirka	0.35
43.	Rania	0.35
44.	Brara	0.35
45.	Buria	0.35
46.	Chhachharauli	0.35
47.	Naraingarh	0.35
48.	Indri	0.35
49.	Beri	0.35
50.	Kalanapur	0.35
51.	Pehowa	0.35
52.	Raipur Rani	0.35
53.	Ganaur	0.45

54.	Mahindergarh	0.45
55.	Bawani Kheara	0.45
56	Julana	0.45
57	Safidon	1.00
58	Hodel	0.45
59	Nuh	0.45
60	Nagina	0.45
61.	Haily Manid	0.45
62.	Pataudi	0.45
63.	Farukh Nagar	0.45
64.	Kalanwali	0.45
65.	Cheeka	0.45
66.	Pundri	0.45
67.	Radapur	0.45
68.	Ladwa	0.45
69.	Shahaura	0.45
70.	Shehzadpur	0.45
71.	Tarauri	0.45
72.	Assandh	0.45

73.	Kharkhauda	0.68125
74.	Saohan	0.68125
75.	Samlkha	0.68125
76.	Gharunda	0.68125
77.	Niolkheri	0.68125
78.	Meham	0.68125
79.	Ratia	0.68125
80.	Ellenabad	0.68125
81	Faridabad Comlex	7.95
	Total	88.00

ANNEURE E

**V. Central incentive grnat for Environmental Improvement
of Urban Stums:**

Sr.No	Name of M.C	Amount of grant Rs. In Lacs
1.	Ambala Ctiy	2.00
2.	Ambala Sadar	2.00
3.	Yamuna Nagar	2.00
4.	Bhiwani	2.00

5.	Gurgaon	2.00
6.	Hansi	2.00
7.	Hissar	2.00
8.	Karnal	2.00
9.	Panipat	2.00
10.	Kaithal	2.00
11.	Thanesar	2.00
12.	Rewari	2.00
13.	Rohtak	2.00
14.	Sirsa	2.00
15.	Sonepat	2.00
16.	Jind	2.00
17.	Kalka	1.50
18.	Jagahri	1.50
19.	Charkhi Dadri	1.50
20.	Palwal	1.50
21.	Fatehabad	1.50
22.	Tohana	6.50
23.	Narwana	1.50

24.	Narunal	1.50
25.	Shahbad	1.50
26.	Bahadurgarh	1.50
27.	Jhajjar	1.50
28.	Mandi Dabwali	1.50
29.	Gohana	2.50
30.	Faridabad Complex	4.00
31.	Pehowa	1.28571
32.	Pundri	1.28571
33.	Ladwa	1.28571
34.	Naraingarh	0.78571
35.	Kharkhauda	28,571
36.	Ganaur	28,571
37.	Mahindergarh	28,571
38.	Kanina	28,571
39.	Bawal	28,571
40.	Loharu	28,571
41.	Tosham	28,571
42.	Bawani Khera	28,571

43	Uklana Mandi	28,571
44.	Jakhal	28,571
45.	Ratia	28,571
46.	Barwala	28,571
47.	Uchana	28,571
48.	Julana	28,571
49.	Safidon	28,571
50.	Kalyat	28,571
51.	Sohna	28,571
52.	Taoru	28,571
53.	Nuh	28,571
54.	Ferozepur Jhirka	28,571
55.	Haily Mandi	28,571
56	Patudi	28,571
57	Farukh Nagar	28,571
58	Rania	28,571
59	Kalanwali	28,571
60	Ellenabad	28,571
61.	Cheeka	28,571

62.	Raipur Ram	28,571
63.	Buria	28,571
64.	Chhachharauli	28,571
65.	Sahhaura	28,571
66.	Shahzadpur	28,571
67.	Samalkha	28,571
68.	Gharaunda	28,571
69.	Pundri	28,571
70.	Nilokheri	28,571
71.	Radaur	28,571
72.	Assandh	28,571
73.	Meham	28,571
74.	Beri	28,571
75.	Kalanpur	28,571
76.	Hodel	28,592
77.	Huthin	28,571
78.	Hassanpur	28,571
79.	Ateli Manid	28,571
	Total	80.00

ANNEURE F

VI. Development

Sr.No	Name of M.C	Amount of grant Rs. In Lacs
1.	Ambala Ctiy	2500
2.	Ambala Cantt	2500
3.	Naraingarh	2000
4.	Yamun Nagar	2500
5.	Jagadhri	2500
6.	Sadhaura	2000
7.	Kalka	2500
8.	Shahbad	2000
9.	Kaithal	2000
10.	Thanesar	2000
11.	Karnal	2500
12.	Indri	2000
13.	Samalkha	2000
14.	Nilokheri	2000
15.	Gharaunda	2000

16.	Panipat	2000
17.	Sonepat	2500
18.	Sohna	2000
19.	Ganaur	2000
20.	Rohtak	2500
21.	Kalanur	2000
22.	Jhajjar	2000
23.	Bahadurgarh	2000
24.	Faridabad City	2000
25.	Hodel	2500
26.	Palwal	2500
27.	Ferozepur Jhirka	2000
28.	Nuh	2000
29.	Hail Mandi	2000
30.	Sohna	2000
31.	Narnaul	2500
32.	Rewari	2500
33.	Ateili Mandi	2000
34.	Bhiwani	2500

35.	Charkhi Dadri	2000
36.	Tosham	2000
37.	Fatehabad	2500
38.	Hansi	2500
39.	Jakhal Mandi	2000
40.	Tohana	2000
41.	Sirsa	2000
42.	Jind	2500
43	Julana	2000
44.	Safidon	2000
45.	Narwana	2000
46.	Kalyat	2000
	Total	100000

ANNEXURE G

VII. Compensatory grant for operating cattle ponds:

Sr.No	Name of M.C	Amount of grant Rs. In Lacs
1.	Yamuna Nagar	258

2.	Sudhaura	3694
3.	Kalka	2052
4.	Hodel	1095
5.	Ladwa	545
6.	Kaithal	976
7.	Thanesar	1165
8.	Rohtak	1360
9.	Meham	811
10.	Rewari	11
11.	Hansi	1190
12.	Fatehabad	70
13.	Sirsa	4621
14.	Ferzepour	3155
15.	Gurgaon	4189
16.	Charkhi Dadri	387
17.	Narnaul	27
18.	Tosham	762
19.	Tohana	322
	Total	29777

ANNEURE H

VII. For the Draings Scheme of Rohtak Town

Name fo M.C	Amount of Grant
Rohtak	128 Lacs

ANNEXURE I

IX four Water Supply Schema

Lic aided schems:-

Sr.No	Name of M.C	Amount of grant Rs. In Lacs
1.	Ambala City	3.50
2.	Bhiwani	1.60
3.	Charkhi Dadri	0.80
4.	Kalanaur	0.80
5.	Rohtak	3.50
6.	Pataudi	0.40
7.	Ellenabd	0.60
8.	Hissar	1.60
9.	Uchana	0.80
10.	Assandh	1.50

11.	Pehoow	1.20
12.	Shahbad	0.80
	Total	1710
II) For non LIC Schemes		
13.	Ambala City	3.90
14.	Ambala Sadar	0.60
15.	Shehzadpur	1.50
16.	Bhiwani	1.00
17.	Ateli Mandi	1.10
18.	Mahendergarh	1.00
19.	Rewari	0.20
20.	Narwana	3.50
21.	Kalyat	1.60
22.	Jind	1.90
23.	Karnal	1.00
24.	Panipat	2.30
25.	Gharaunda	1.70

26.	Samalkha	1.80
27.	Indri	1.80
28.	Thansher	0.80
29.	Jhajjar	1.70
30.	Beri	1.40
31.	Meham	1.10
32.	Haily Mandi	1.40
33.	Farrukh Nagar	0.20
34.	Hodel	1.50
35.	Uklana Mandi	1.90
36.	Kharkhauda	1.90
	Total	36.80
(III) New Scheme		
37.	Sadhaura	0.40
38.	Naraningarh	0.80
39.	Jakhal	1.10
40.	Fathebad	1.60
41.	Jind	0.80
42.	Sonepat	1.50

43	Narnaunal	1.50
44.	Pundri	0.80
45.	Gurgoan	0.50
46.	Karnal	2.00
47.	Tosham	1.10
	Total	12.10

Grand Total of (i) (ii) and (iii) = 66.00 Lacs

ANNEXURE J

For Sewarage Scheme

(I) LIC added Scheme

Sr.No	Name of M.C	Amount of grant Rs. In Lacs
1.	Panpati	1.60
2.	Rohtak	2.00
3.	Gurgaon	1.30
	Total	4.90
(ii) Non LIC added Scheme		
4	Naranigarh	1.20

5.	Yamunenagar	1.60
6.	Shahbad	1.60
7.	Safidon	1.60
8.	Uchana	1.30
9.	Bahadurgarh	1.60
10.	Tohana	2.80
11.	Fatehabad	0.80
12.	Uklana Manid	1.50
13.	Sonipat	0.80
	Total	14.80
(iii) New Scheme		
14.	Narwana	1.90
15.	Jind	2.10
16.	Karnal	2.30
17.	Gharnaund	1.20
18.	Samalkha	0.80
	Total	9.30

Grand Total of (i) (ii) and (iii) = 29.00 Lacs

**Overhead Supply Reservoir of Water in Safidon
Mandi**

204. Chaudhir Kundal Lal: Will the Minister for Public Health be pleased to state whether there any proposal under consideration of the Government to construct an over head supply reservoir of water in Safidon Mandi if so the time by which the said proposal is likely to be materialized ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): नहीं। पानी का उर्ध्ववर्ती प्रदाय जला टाय औवर हैड सर्विस रिजर्वायर आफ वाटर का निर्माण सफीदो नगर में पहले हो चुका है तथा यह सफीदो नगर एवम सफीदो मंडी दोनों की मांग को पूरा करता है।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

15.00 बजे

श्री लक्ष्मण सिंह: स्पीकर साहब, पिछले सैं आन के बाद कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे हैं जैसे पंजाब का एकोर्ड है इन फैसलों के मुताबिक चण्डीगढ़ पंजाब को चला गया है। इस फैसले के बाद हरियाणा के लिए नई कैपिटल की प्रोबलम खड़ी हो गई है आजकल यह बहस का मौजू बना हुआ है पता नहीं चीफ मिनिस्टर साहब मेरी कास्टीच्यूएंसी के साथ क्यों नाराज हैं? ये कहते हैं कि पंचकूला को कैपिटल के लिए कसीडर नहीं करेंगे। मेरी दख्तास्त है कि ये इसका कारण बताए कि इनको पंचकूला से क्या एलर्जी है। यह पर क्लेम भी कम

देने पडेगे। जों हिसार के अन्दर गरदोगवार है उससे यह बहुत बढिया जगह है। तो स्पीकर साहब, मै चीफ मिनिस्टर साहब से एक दो बाते अर्ज करना चाहता हू क्या वजह है कि पचकूला को इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद भी कैपिटल के लिए कसीडर नहीं किया जा रहा है। चौधरी बंसी लाल ने पचकूला इसीलिए बनाया था कि अगर चण्डीगढ पजाब को चला गया तो पचकूला को हरियाणा की राजधानी बनाएगे। दूसरे कल पजाब के चुनाव मे अकालियों की थम्पिंग मैजोरिटी को देखते हुए यह चर्चा चल रही है कि हरियाणा सरकार अपनी टैम्पोरेरी राजधानी कही पर जल्दी ले जाना चाहती है। मै सरकार से कहूंगा कि पचकूला के बढिया जगह और कोई नहीं है। यहा पर सरकार का खर्चा भी कम आएगा। सिक्थोरिटी रीजज की वजह से अगर इन्होने 26 जनवरी से पहले जाना हो तो टैम्पोरेरी राजधानी के लिए पचकूला सबसे बढिया जगह है। स्पीकर साहब, मै आपको याद दिलाना चाहता हू कि जब पार्टी 1 न हुई थी तो पंजाब सरकार लाहौर मे िमला गई थी। वहां 4-5 साल रही, उसके बाद चण्डीगढ को सिलैक्ट किया गया और यहा पर िफ्ट कियां। इसलिए ये भी पचकूला मे टैम्पोरेरी राजधानी बना सकते है। उसके बाद इनकी कैबिनिट जा चाहे जा सकते है इसमे किसी को एतराज नहीं होगा। ऐसा करने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा बल्कि कांग्रेस पार्टी के ज्यादा वोट बढेंगे। यानी मेरे को पोलिटीकल गेन नहीं होगा बल्कि इनकी पार्टी को होगा। एक बात मै और कहना चाहता हू जिसे मेरे कांग्रेस के भाई भी महसूस

करते होंगे। कल से हम यह महसूस कर रहे हैं कि भायद आपने अपने अख्तियार विधान सभा की बाऊडरी के अन्दर न बन्द कर दिए हों। पुलिस जगह जगह हमारी कारों को रोक लेती है। एम0एल0ए0 होस्टल और फ्लैट्स में भी डिटेक्टर लगे हुए हैं हम अपने फ्लैट में दस बार जाए या बीस बार जाए तो उतनी बार ही नाम लिखते हैं मैं समझता हूँ कि यह आपकी जुरिसाडिक एरिया में है। जब चण्डीगढ़ पंजाब को ट्रांसफर होगा तब देखा जाएगा। इस समय किसी को कोई खतरा नहीं है यह सब महसूस करते हैं कि अभी इतनी सिक्योरिटी का कोई रीजन नहीं है। मेरे खुद के पास कोई गार्ड नहीं है और न मेरे को किसी से कोई खतरा नहीं है ठीक है। वी.आई.पी. के लिए इतना जाम किए जाते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसको बहुत बड़ा हौवा बना दिया जाए। इसके आलावा जो एम.एल.ए. से एरिया अटैण्ड करने के लिए हाउस में आते हैं उन्हें अपनी गाड़ियों पार्क करने के लिए बड़ी कठिनाई आती है। इस बारे में ड्राइवर्ज को बहुत परेशान किया जाता है कभी कहते हैं गाड़ी इधल ले जाओ, कभी कहते गाड़ी उधर ले जाओ। एम.एल.ए. होस्टल के अन्दर भी इस बारे में बहुत दिक्कत है विज साहब यहाँ बैठे हुए हैं बुढ़ापे में इनको बड़ी भारी इन कनविनिअंस है आप इनसे इस बारे में पूछें तो स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब में दरखास्त करूंगा कि पंचकूला को टैम्पोरेरी कैपिटल बनाने के बारे में जरूर गौर फरमाएं। इन्होंने महीने में या 15 दिन में कैपिटल जरूर रिफिट करनी है। और कैपिटल जल्दी रिफिट करने के काइ कारण हो सकते हैं मुझे इस

बारे में कुछ पता नहीं है चीफ मिनिस्टर साहब को पता हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर साहब कहेंगे वही होगा। स्पीकर साहब, मैं आपसे भी दरखास्त करूंगा कि आप भी चीफ मिनिस्टर साहब से यह सिफारिस कर दें कि टैम्पोरेरी कैपिटल पचकूला में फिट कर दी जाए। मेरे हल्का भी आपके हल्के के नजदीक ही लगता है, कोई लम्बा चौड़ा एरिया नहीं है। मेरे हल्के में आपके हल्के में जाने का केवल एक घंटे का ही रास्ता है।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, सरदार लछमन सिंह जी ने मेरे मुताल्लिक कुछ कहा है। मैं भी यह कहना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूटर से यानि थ्री व्हीलर से एम.एल.एज. होस्टल में आया तो उस समय सरदार लछमन सिंह जी वहाँ पर थे। मैं जिस थ्री व्हीलर में आया उसको पुलिस वालों में एम0एल.एज0 होस्टल के सामने जो फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स के कौने पर मेरस स्कूटर खड़ा कर लिया और आगे नहीं जाने दिया। मैं स्कूटर से नीचे उतर कर अपना सामान लेकर जब एम0एल0ए0 होस्टल में आया तो वहाँ पर मुझे खड़ा कर लिया और कहने लगे कि सामान खोल कर दिखाओ हमारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। मेरे सामने उस समय दो तीन मिनिस्ट्रों की कारें आईं, उनको किसी ने चैक नहीं किया और न ही किसी ने उनकी कार रोकੀ। उनसे किसी ने यह नहीं पूछा कि आपके पास क्या है। लेकिन स्पीकर साहब, हमारे साथ यह भेदभाव किया जा रहा है। इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेरे सामने दो तीन मिनिस्ट्रों की

कारे आई थी उनकी किसी ने नहीं पूछा कि किस तरफ जा रहे हैं। स्पीकर साहब, एम0 एल0 एज0 होस्टल का यह हाल है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत है। इसके अलावा, सरदार लछमन सिंह जी ने मेरे मुताल्लिक बुढापे के बारे में कोई बात कही। मैं इनको कहना चाहूंगा कि इन्होंने तो अपने सफेद वालों को रंग लगाया हुआ है इसलिए इनका पता नहीं लगता। इनकी पगडी बहुत सफेद है लेकिन इनका दिल काला है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, पिछले सैंान और इस सैंान के बीच में एक बहुत अहम मामला 24 जुलाई को हुआ था। उस दिन हरियाणा प्रान्त के हितों का कत्ल हुआ था उस दिन हरियाणा के हितों की जो बात थी उनको सुना तक नहीं। उस बात को लेकर इस सदन के आनरेबल मैम्बरो ने अपने इस्तीफे किए। उनमें से दो बड़े नेताओं के अस्तीफे मजूर कर लिए गए और उन जगह पर उप चुनाव भी कराए गए हैं मुख्य मंत्री जी उस मधे पर जनता के समाने मैन्डेट के लिए गए। जिन दो जगहों पर उप चुनाव कराए गए हैं, उनमें से एक जगह रोहतक में हमारे साथ सरकार ने बड़ी भरी ज्यादाती की है। पिछले चुनाव में डा0 मगल सैन जी को 19 हजार वोट मिले थे उस समय वे चुनाव जीत गए थे। इस उप चुनाव में उनको 32 हजार वोट मिले हैं यानि रोहतक के 32 हजार लोगों ने उस फैसले को पसंद नहीं किया जो फैसला 24 जुलाई को किया गया था। उन लोगों ने

यह कहा कि यह फैसला बिल्कुल गलत किया गया है इसमें हरियाणा के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं एक बात और आपके सामने कहना चाहूंगा। इसी महीने की 24 तारीख की रात को पुलिस की मौजूदगी में 500 लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया। हमने पुलिस को फोन किया और पुलिस वहां पर आई। हमने वहां के ए० एस० पी० को उस हमले के बारे में सारी रिपोर्ट दी।

श्री अध्यक्ष: यह बात तो आप पिछले इलैक्ट्रॉनिक्स की कर रहे हैं।

श्री राम बिलास भार्मा: नहीं जी। मैं इसी चुनाव की बात कर रहा हूँ जो अभी दो दिन पहले यानी 25 तारीख को हुए हैं। तो स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वहां पर इस तरह से जनमत को दबाने की और जनमत को प्रलोभन देने की कोशिश की गई है। 24 जुलाई को जो फैसला किया गया, उसमें हरियाणा के हितों का कत्ल किया गया। जब इस तरह का कोई फैसला होता है तो सरकार उस पर जनता का मैनडेट लेती है कि यह फैसला ठीक है या गलत है। यह फैसला गलत हुआ इसलिए हमने अपने इस्तीफे दिए। (गोर)

आवाजे: आपने इस्तीफे कहा दिए ? (गोर)

श्री राम बिलास भार्मा: हमने तो नहीं दिए लेकिन हमारे लीडर्स ने तो इस्तीफे दिस हैं। जिस तरह से उन जगहों पर उप

चुनाव हुए है वह बहुत गलत तरीके से हुए है वहा पर हमारे साथ बड़ी ज्यादाती हुई है आज इस सरकार को रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है यह सरकार हरियाणा के हितो की रक्षा नहीं कर सकी इसलिए इसको बने रहने का कोई अधिकार नहीं है । स्पीकर साहब, 8 नवम्बर 1983 को हरियाणा भवन दिल्ली मे एक मीटिंग हुई थी जिसमे खुद चौधरी भजन लाल जी थे और इनके साथ चौधरी देवी लाल जी और डा० मंगल सैन जी भी थे। उस समय इन तीनों ने बैठ कर यह कहा था कि यदि हरियाणा के साथ टैरीअरी के मामले मे, पानी के मसले पर और कैपिटल के मामले मे कोई ज्यादाती हुई तो हम सब इस्तीफे दे देगे। It was published in national press. A particular phrase was used “ We will sink and swim together” particularly for this accord. उसके बाद हमारे दोनों नेताओ ने उस पर अमल करते हुए उस फैसले के खिलाफ अपने इस्तीफे दिए। उस समय मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने भी इस्तीफा देने के बारे मे बात कही थी, इनको अपनी कही हुई बात पर अमल करना चाहिए था। आज ये किस हैसियत से मुख्यमंत्री है? मै यह कहना चाहता हू कि उस फैसले के बारे मे इनका जनता से जो मैनडेट लेने का तरीका था, वह बहुत गलत था। रोहतक मे जिस तरह से नहीं होना चाहिए था पर्टीकुलरली जो ज्यादाती हुई है वह हमारे साथ हुई है स्पीकर साहब, आप तो हमारे अधिकारी के कस्टोडियन है पुलिस हमारी दरखास्त पर कोई अमल नहीं करती है। हमने पुलिस से कई बार रिक्वैस्ट भी की कि लोग हमारे साथ, हमारे आफिस मे आ कर

लगातार दंगा फसाद कर रहे है लेकिन पुलिस की मौजूदगी मे 500 लोगों ने हमारे आफिस मे आ कर हमारे ऊपर हमला किया। हमने उस बारे मे पुलिस की रिपोर्ट दी लेकिन उस बारे मे कोई कार्यवाही नही हुई। सरकार ने अपने तरीके से वह मुकदमा दर्ज कर लिया। स्पीकर साहब, मै आप के द्वारा मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी से कहना चाहता हू कि नैतिकता का तकाजा है कि किसी के साथ इस तरह से नही होना चाहिए। चौधरी भजन लाल जी आपने स्वय हाथ उठा कर यह बात कही थी कि यदि हरियाणा के हितो के साथ कोई ज्यादाती हुई है तो सब मिल कर अस्तीफे दे देगे। राजस्थान के मुख्य मंत्री उस फैसले के बारे मे कहा था कि जो पानी के बारे मे फैसला हुआ है, वह मुझे राजस्थान के मुख्यमंत्री की हैसियत से मजूर नही है इसलिए चाहिए तो वह था कि चौधरी भजन लाल जी भी यह कहते हमे पूरा पानी मिलना चाहिए। लेकिन जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक तो हरियाणा का पानी का हिस्सा 35 लाख एकड फीट से 12 लाख एकड फीट हो गया है। और कैपिटल के मामले मे कोई चर्चा ही नही की गई। Not even a single wrold was used about the cpital. The date was fixed i.e 26th January 1986 which will be the final date to transfer Chandigarh to Punjab. We are a State. We have been having our Secretariat here. हम कहा जाएगे? यह इनको सोचना चाहिए।

Mr. Speaker: Please Close it now.

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, जब वह फैसला किया गया उस समय हमारी कैपिटल के बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए थी।

Mr. Speaker: No repetition Please.

वाक आउट

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, इनको उस फैसले का विरोध करना चाहिए था। हरियाणा की टैरीटरी के बारे में स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधी जी भाहीद हो गई उन्होंने हरियाणा को 119 गांव देने के लिए दस्तखत किए थे। जो अब फैसला किया गया है उसमें जिन गांवों के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने दस्तखत किये थे, उनके बारे में यह कह दिया कि now the village will be the unit and not a group of villages, और फैसले में अबोहर और फाजिल्का हरियाणा को न देने की बात है वह फैसला सरासर गलत हुआ है। उस फैसले से हरियाणा की बहुत हानि हुई है और उसमें हरियाणा के हितों का कत्ल करके रख दिया गया है इसके बावजूद भी ये लोग बड़ी दिलीरी से जनता का मैनडेट लेना चाहते हैं। जो फैसला हुआ है वह हरियाणा के हितों के बिल्कुल खिलाफ है इन्होंने लोगों की मैनडेट लेने में कोई ग्रेस नहीं दिखाई। इस सरकार के इस तरह से रवैये के खिलाफ हम वाक आउट करते हैं

इस समय भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में वाक आउट कर गए।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री श्री किान दास द्वारा

श्री श्री किान दास: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य श्री राम बिलास भार्मा ने यह बात कही कि रोहतक के चुनावों में हमारे साथ ज्यादाती हुई है। स्पीकर साहब, इन्होंने रोहतक में मेरी पार्टी के एक आदमी को चाकू मारा वह आदमी रोहतक मैडीकल कालेज में दाखिल है। उस आदमी को श्री राम बिलास भार्मा की मौजूदगी में चाकू मारा गया। आप चाहे इस बारे में पता कराले।

श्री अध्यक्ष: मुझे एक घंटे से पता था कि इनको वाक आउट करना है इन्होंने अपनी स्कीम पूरी कर दी।

श्री श्री किान दास: स्पीकर साहब, इनकी पार्टी का एक आदमी तो रोहतक में कल वाक आउट कर गया और ये भी इस तरह से चले जाएंगे। (गोर) इन्होंने रोहतक को जनता कालोनी में दंगा फसाद किया, एक आदमी को चाकू मारा, वह मैडीकल कालेज रोहतक में दाखिल है इनके किसी भी आदमी को कोई चोट नहीं लगी है और न ही कोई दंगा फसाद किया गया है गवर्नमेंट हमारी पार्टी की कहलाती है इसलिए ये इस तरह की बता कर रहे हैं। कल चौधरी देवी लाल जी ने हमारे दो आदमियों को पिटाया, उनमें से एक आदमी मैडीकल कालेज रोहतक में पडा है आप चाहे इस बारे में पूछताछ कर लें। लेकिन लोगों को हमारी पार्टी में विश्वास था, इसलिए लोग इनकी जबरदस्ती में नहीं

आए। इन्होंने रोहतक में दो आदमियों को सड़क पर पीटा। उनमें से एक आदमी को ट्रॉंग टूट गई और एक आदमी का सिर फोड़ा दिया। आप चाहे इस बारे में पता करवा लें। इनकी पार नहीं बसाई जब मैं 1972 में इलैक्ट कर आया था उस समय डा० मंगल सैन कहा गए थे? जब वहाँ के लोग मेरे साथ हैं तो ये कुछ नहीं कर सकते। हम इनकी बातों पर विवास नहीं करते।

वक्तव्य

(1) मुख्य मंत्री द्वारा पंजाब समझौता तथा राज्य की राजधानी के स्थान के चयन तथा सुरक्षा अमले द्वारा विधायकों की तलाशी संबंधी।

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सरदार लखमन सिंह जी ने और बी०जे०पी० के एक भाई श्री राम बिलास भार्मा जी ने सदन में कुछ बातें कही।

श्री लक्ष्मण सिंह: चौधरी साहब, मेरी बात का आप अलग जवाब दें।

चौधरी भजन लाल: पहले मुझे श्री राम बिलास भार्मा की बात से ही भ्रू करना पड़ेगा, आपकी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री राम बिलास भार्मा ने सरकार का इल्जाम लगाया कि सरकार ने रोहतक वार्ड इलैक्ट्रान में इनके साथ ज्यादाती की इस बात का जवाब रोहतक से चुनकर आये हुए। एम०एल०ए० श्रीकिशन दास ने दे दिया है, मुझे ज्यादा कहने की

जरूरत नहीं । दिल्ली अकोर्ड के बारे में लोक दल और बीजेपी वाले भाईयो द्वारा मगरमच्छ के आसू बहाये जाने के बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, यह अकोर्ड ने इन के हित में बहुत ही भानदार अकोर्ड है क्या हालत थी मूलक में, इस बात की आप सभी भली भाती जानते हैं ने इन के हित में एक फैसला हुआ और उस फैसले को अकेले हरियाणा प्रदेश की जनता ने ही नहीं बल्कि सारे देश के लोगो ने स्वागत किया । इतना ही नहीं बाहर के मुल्को ने भी प्राईम मिनिस्टर को मुबारिकबाद दी है कि प्राईम मिनिस्टर ने सत लोगोवाल के साथ बैठकर एक बहुत ही भानदार फैसला किया है और पजाब समस्या का बहुत अच्छा हल निकाला है जहा तक हरियाणा प्रदेश के हितो का सवाला है अध्यक्ष महोदय हमने इस फैसले के बारे हाउस में भी बाहर भी कहा है कि हरियाणा के हित बिल्कुल सुरक्षित है । महसूस करेगे कि कितना भानदार फैसला हुआ है । इस सिलसिले में अगर तफसील से कहू तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि यह केस कमी इन के पास जेरेगगौर है इससे ज्यादा कहना मेरे लिये उचित नहीं है ।

श्री लछमन दास: आपको कैसे पता लगा गया कि यह फैसला हरियाणा के हित में है?

चौधरी भजन लाल: डिटेल में कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है आपने अकोर्ड में टर्म्ज आफ रैफ्रोसिज देखी होगी । अकालियो ने मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया है कि सैन्टर के साथ

मिलकर मैं टर्म्ज आफ रैफ्रैसिंज चेज कर रहा है। इससे साफ जाहिर है कि अकाली पहले से ही अपनी पें अबन्दी कर रहे हैं। मैं यह कहता हूँ कि हरियाणा के साथ इन्साफ होगा। हरियाणा को किसी किमत पर नुकसान नहीं हो सकता, चाहे पानी का मसाला हो, चाहे चण्डीगढ़ के बदले में हिन्दी भाषी इलाके मिलने का मसला हो, हरियाणा के साथ बेइन्साफी नहीं होगी। कमी आन का फैसला हरियाणा के हित में हुआ है इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मामला कमी आन के पास है आज ये भाई सदन से वाक आउट कर गये। इनके एक नेता ने असेम्बली में अस्तीफा दे दिया जबकि वे अस्तीफा देना नहीं चाहते थे वे चौधरी देवी लाल के जाल में फस गये और अस्तीफा दे बैठे। अध्यक्ष महोदय, 1982 के इलैक् आन में रोहतक कास्टीच्यूसी से कांग्रेस के उम्मीदवार को साढ़े 19 हजार वोट मिले थे लेकिन इस वार्ड इलैक् आन में 37000 वोट मिले हैं। पब्लिक ने हमारे उम्मीदवार को इस बार 1982 के वोटों के मुकाबले दुगुने वोट दिये हैं इतने वोट क्यों दिए ? पब्लिक ने इस अकौर्ड को स्वीकार किया है देहात के लोगों ने भी स्पोर्ट किया । अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा चौधरी देवी लाल मेहम कास्टीच्यूसी से 1982 में 17 हजार वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार इलैक् आन में 11 हजार से जीते हैं इस बार इनको 6 हजार वोट कम मिले हैं। इनके मुकाबले में 1982 में कांग्रेस उम्मीदवार को 19 हजार वोट मिले थे और इस बार साढ़े 27 हजार वोट मिले हैं यानी पहले के मुकाबले में 85000 वोट फालतू मिले हैं ये इस लिये मिले हैं कि लोगों ने दिल्ली अकौर्ड

का स्वागत किया है। इसके इलावा, इस बाई इलैव न मे चौधरी देवी लाल ने किस तरह जातिवाद का जहर फैलाकर लोगों से वोट लिये, यह सभी जानते हैं लोगो से कहते थे कि मेरी जिन्दगी और मोत का सवाल है मेरी इज्जत बचाओ, मुझे वोट दो अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपके द्वारा सदन को बता देता हू कि इस प्रदेश के सभी लोगो ने चाहे वह गरीब आदमी था चाहे वह आम आदमी था सब लोगो ने एक जुट होकर इस फैसले को स्वीकार किया। बैकवर्ड क्लासिज के भाईयों ने हरिजन भाईयो ने पजाबी भाईयो, यानी जितने भी जातियों के लोग हैं सभी ने इस फैसले का स्वागत किया है। लेकिन इन्होंने जातिवाद का जहर फैलाकर वोट लेने की कोशिश की है लोगो ने डट कर इस फैसले का स्वागत किया और कांग्रेस के कंडीडेट को पहले से ज्यादा वोट दिये।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सदन से अस्तीफा दे दिया और हरियाणा के केस को कमजोर करने की कोशिश की। इनका यह फर्ज नहीं था कि हरियाणा के केस को कमजारे करे। हरियाणा का एम0 एल0 ए0 होने के नाते अगर हरियाणा के केस को प्लीड करते तो अच्छा था। अगर कोई बेइन्साफी होती तो वे इसके खिलाफ आवाज उठा सकते थे कि हरियाणा के साथ बेइन्साफी हुई है लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया जो भी आवार्ड हुआ है उसके मुताबिक कमी न बैठे हुआ है, उस कमी न की टर्मज आफ रैफरेंसिज है। यह फैसला दोनों प्रदेशों के हित में भारत

सरकार ने किया है प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और सन्त हरचन्द सिंह लोगोवाल ने बैठ कर यह फैसला सारी नै उन के हित मे और दोनो प्रदे गो के हित मे रखकर किया है लेकिन चौधरी देवी लाल हमारे अकाली भाईयों से हमें गो से ही मिले हुए रहे है यह बात मै नही कहता यह रिकार्ड की बात है। अध्यक्ष महोदय आपको याद होगा पिछले सै उन मे चौधरी देवी लाल ने कहा था कि पजाब मे अकालियों की सरकार बननी चाहिए। जब दिल्ली अकौर्ड हुआ तो चौधरी देवी लाल ने डा० मंगल सैन और दूसरे सदस्यों को साथ मिलाकर अस्तीफा दे दिया। अस्तीफा देकर यह साबित करने की कोशिश की कि हरियाणा के इन्ट्रस्ट सेफ नही है अंस्तीफा इसलिए दिया ताकि पजाब के लोग समझे कि अकालियों ने बडा भारी मोर्चा जीत लिया है। यह पौलिटिक्स की बात है, आप सभी जानते है कि इससे इलैव उन मे अकालियो को लाभ हुआ। जहा तक डा० मंगल सैन और दूसरे सदस्यो के अस्तीफे देने का सवाल है, इस पर मै एक मिसाल देता हूं एक ब्राहाण गांव मे स्नान करने के लिए चल पडा। सर्दी के दिन थे। पडित जी रोज स्नान करते थे ठडे पानी से। भाकरुल्ला खां बैठे है इनकी वरादनी का एक भाई भी पडित जी के साथ गंगा स्नान के लिए चला गया। जग गंगा मे नहाने लगे तो उस भाई को ठडे पानी से बुरा हाल हो गया। पडित जी नहाते समय कहने लगे हर हर गगे हर हर गगे। दूसरी तरफ वह भाई ठडे पानी से तंग होकर कहने लगा मैने क्यो लिया पंगा। वह बेचारा खाहमखाह फस गया था। अध्यक्ष महोदय इसी तरह से ये भाई अस्तीफे देकर फस

गये है। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, हमने कमीान के सामने फाजिल्का और अबोहर के 410 गावों को हरियाणा के भामिल करने के लिए क्लैम किया है हमे चण्डीगढ के बदले मे ये 410 गांव मिलने चाहिये लेकिन इस बात का कमीान ने फैसला करता है जो ठीक बात होगी, उसी हिसाब से कमीान फैसला करेगा।

अध्यक्ष महोदय, जहा तक हरियाणा कैपिटल का सवाल है इसके बारे मे सरदार लछमन सिंह जी दो बाते कही । एक टैम्परेरी कैपिटल के बारे मे और एक परमानैट कैपिटल के बारे मे। जहां तक परमानैट कैपिटल का ताल्लुक है इस का फैसला हम तभी करेगे जब मैथयू कमीान अपना फैसला दे देगा। कमीान के फैसला देने के बाद ही हरियाणा कैपिटल के बारे मे सोचेगा। इस मक्सद के लिए हमने हाई पावर्ड कमेटी बना रखी है जिसमे सीनिय आफिसर और टैक्नीकल मैम्बर है जो एक एक बात को गहराई से देखेगे। आपने हिसार के बारे मे बात कह दी। लेकिन मै आपको बताना चाहता हू कि हमारे लिए सारा प्रदेा एक समान है जहां ठीक बात होगी, मुनासिब बात होगी वहा कैपिटल बनना चाहिए। कहा पानी अच्छा है जमीन उपलब्ध है ये सारी बाते देखने पडेगी आपने यह भी कहा कि मैने यह क्यो कहा कि पचकूला मे कैपिटल बनाने की बात विचारधीन नही है मै मानता हू कि मैने यह कहा था मैने यह इसलिए कहा था कि जब हम चण्डीगढ छोड देगे तो पचकूला मे कैपिटल बनाने के कोई मायने नही है। आप जानते है कि यह एक कोने मे पडता है चण्डीगढ से अगर हम

जाते हैं तो कैपिटल ऐसी जगह होनी चाहिए जहां प्रदेश के लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके। वे सुबह आए और भाम को अपने घर जा सके लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस बारे में हम अपोजिशन के भाईयों को विश्वास में लेंगे। सारी कैबिनेट इस सम्बन्ध में फैसला करेगी पार्टी फैसला करेगी और जो मुनासिब बात होगी वह हम करेंगे ताकि कोई यह न कह सके कि किसी जिले के साथ ज्यादाती हो गई कोई अन्याय की बात हो गई। हम किसी के साथ अन्याय की बात नहीं करेंगे। जो मुनासिब बात होगी जहाँ सब समझेंगे कि कैपिटल बनना चाहिए वहाँ कैपिटल बनाएँगे।

श्री लखमन सिंह: कैपिटल का फैसला क्या आप मैथ्यू कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद करेंगे ?

चौधरी भजन लाल: जी हाँ।

श्री निहाल सिंह: कुछ जिलों के नाम तो आप बिल्कुल ही नहीं लेते।

श्री लखमन दास: अम्बाला के बारे में भी आप कुछ नहीं कहते। (विधन)

चौधरी भजन लाल: सरदार लखमन सिंह जी अगर अम्बाला जिले में राजधानी बनाने की बात हो, फिर तो पचकूला हमारे पास बनी बनाई राजधानी है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा माइन्ड ओपन है लेकिन आप जानते हैं कि

अम्बाला जिला भी एक साइड मे पडता है चूकि यह एक तरफ पडता है इस लिए बडी दिक्कत पडेगी। इस तरह तो कुछ लोग नारनौल की बात करते है कुछ गुडगांव, फरीदाबाद, और सिरसा की बात करते है इन सब बातो को हाई पावर्ड कमेटी देख लेगी और सोच समझकर अपनी राय देगी।

जहा तक टैम्परेरी राजधानी का ताल्लुक है इसके बारे मे मै इतना कहूंगा कि अभी चडीगढ को छोडने की बात नही है 26 जनवरी 1986 को यह एरिया पजांब को ट्रास्फर होगा। उसके बाद सोचगे कि कैपिटल कहा बनना चाहिए। अभी यह सोचने की बात नही है आरजी कैपिटल बनना चाहिए या हमे वहा से जल्दी िफ्ट करना चाहिए फ़ैसले मे ऐसी कोई कडी ान नही हैं इसलिए अभी कोई ऐसा विचार नही है कि हम यहा से एकदम चले जाएगे। एकदम जाकर हम कहा बैठेग ? यह अच्छी बात है कि पजांब मे अब सरकार अकालियों की बन जाएगी । भारत मे प्रजातन्त्र है लोगो ने जब उन्हे बहुमत दिया है तो उनकी सरकार अव य बनेगीं। बहुत से लोग हमे डराते है कि हमको अब यहा नही रहना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात नही है अकाली हमारे भाई है वे इस दे ा के वासी है और हम भी इस दे ा के वासी हैं वैसे भी यह पहले वाले फ़ैसले मे है कि पांच साल तक हरियाणा यह रह सकता है। रहने मे हर्ज भी कोई नही है इस पांच साल तक हरियाणा यहा रह सकता है। रहने मे हर्ज भी कोई नही है इस लिए हम को ि ा ा करेगे कि जब तक हमारी कैपिटल

नहीं बनती तब तक हम अपनी कैपिटल यही रखें। भारत सरकार से हम इस बारे में बातचित करेंगे। फिर कुछ लोग कहने हैं कि जब चण्डीगढ़ का कंट्रोल पंजाब को चल जाएगा तो सेफ्टी प्वायट आफ व्यू से हमें यह नहीं रखना चाहिए। लेकिन जब तक हमारी कैपिटल नहीं बनती हम भारत सरकार से प्रार्थना करेंगे कि चण्डीगढ़ तक भारत सरकार का कंट्रोल वैसे ही रहे जैसा आज है। ऐसा कंट्रोल अगले दो-तीन साल तक रह जाए। इसमें क्या दिक्कत है ? इस पीरियड में हम अपनी कैपिटल बना लेंगे। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूँ कि अगर हमें आरजी कैपिटल बनानी पड़ेगी तो पचकूला में हमारे पास काफी जगह है। इस मामले में हमारा माईड ओपन है और हम पचकूला को भी कंसीडर करेंगे। इसके अलावा कई जगहों और भी हैं।

अध्यक्ष महोदय एक बात यह पर एम० एल० एज० की चैकिंग के बारे में कही गई। इस सम्बन्ध में मैं हाउस को बताना चाहूँगा कि यहाँ या तो यू०टी० वालों का कंट्रोल है या स्पीकर साहब का कंट्रोल है लेकिन मैं एक बात अब यह कहना चाहता हूँ कि और आप भी महसूस होंगे कि एम० एल० ए० होस्टल में तो और भी ज्यादा चैकिंग की जरूरत है क्योंकि वहाँ कोई भी आदमी आकर कुछ भी नुकसान कर सकता है इंदिरा गांधी जी का कत्ल उन्हीं बोडी गार्डज ने किया, रक्षा करने वालों ने किया, रक्षक ही भक्षक बन गए। आप किसका वि. वास करेंगे ? फिर आप देखें

सन्त हरचन्द सिंह लोगोवाल की हत्या उन्ही की बिरादरी के लोगो ने कर दी।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: सरदार लछमन सिंह जी खुद होस्टल मे नही ठहरेत। ये तो दो चार आदमियों को खुा करना चाहते है वे चारो आदमी होस्टल मे ठहरते लेकिन उनमे से किसी ने मुझे कभी कोई कप्लेन्ट नही की कि हमे यह दुख है इनकी सेफटी को देखना मेरी ड्यूटी है एम एम0एल0ए0 एक लाख लोगो का नुमायदा होता है और किसके पिछे कौन फिर रहा है वह मुझे पता है पुलिस वाले मुझे भी एक बार रोक लेते है लेकिन मै इस बात का बुरा नही मानता क्याकि मुझे पता है कि ला एण्ड आर्डर मेनटेस करने की बात है उस प्वायट आफ व्यू से चैकिग करना ठीक है।

चौधरी भजन लाल: आपको को तो स्वय कहना चाहिए कि चैकिग कर लीजिए इससे वे दूसरे लोगो की भी चैकिग कर सकते है। आज के हालात मे आप किसी का विावास नही कर सकते ।

श्री ए0 सी0 चौधरी: एम0 एल0 एज0 की तला गी लेने का क्या मतलब है आपको इडिविजुअल की रिसपैक्ट भी मेनटेन करनी पडेगी । क्या कोई एम0एल0ए0 बम अपने आपको गोली मारने के लिए लाएगा ?

चौधरी भजन लाल: आपको खुद यह कहना चाहिए कि हमारी तला ि लीजिए। सेफटी प्वायट आफ व्यू से आपको खुद कहना चाहिए कि आप हमारी तला ि ले ताकि दूसरे लोगो की भी वे तला ि ले सके। आप जानते है कि पिछले दिनो चण्डीगढ मे भी और दिल्ली मे भी कितने लोग पकडे गए। ललित माकन और अर्जुन दास वाली बात भी आपके सामने है इसी तरह से कितने और लोगो की बाते आपके सामने है। इसलिए हर आदमी की सेफटी का इन्ताजम करना जरूरी है फिर भी हम यह कहेगे कि पुलिस चैकिग करते वक्त एम0 एल0 एज0 का ध्यान रखे।

इन भाब्दो के साथ अध्यक्ष महोदय मै इतना कहना चाहता हू कि हरियाणा के हित प्रधान मंत्री जी के हाथो मे सुरक्षित है। उनके होते हुए हरियाणा को नुकसान होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अभी अकौर्ड के बारे मे मुख्यमंत्री ने काफी कुछ बताया। लेकिन एक बात की मै और क्लैरिफिके िन चाहता हूं अकौर्ड तो 26 जनवरी को लागू हो जाएगा। क्योकि उस दिन चण्डीगढ पजाब को हैड ओवर हो जाएगा और चण्डीगढ का ऐडिमिनिस्ट्रे िन पजांब के पास चला जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि हम प्रधान मंत्री जी को रिक्वैस्ट करेगे कि 26 जनवरी के बार भी कुछ अर्से के लिए हमारे औफिसिज, असैम्बली, सैक्रिटेरियरट और डायरैक्टोरेस आदि यहा

हो रहे जाए लेकिन उस हालत मे तो करोडो रूपए किराया हमे देना पडेगा । क्या इस बारे मे भी सरकार ने कुछ सोचा है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष: आप कृपया बैठिए। चौधरी कवल सिंह जी की बात भी सुन लेते है। उसके बाद आप इकट्ठा ही जवाब दे देना।

चौधरी भजन लाल: ठीक है जी।

श्री कवल सिंह: स्पीकर साहब, मै दो बाते कहना चाहता हू एक तो मै यह कहना चाहता हू कि आज से तीन साल पहले गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा फैसला यिका था वह फैसला यह था कि 15.9.1982 को जिन क्लास III ऐम्पालाईज की दो साल की सर्विस हो गई थी उनको परमानैन्ट कर दिया था लेकिन क्लास II औफिसर्ज की तरफ सुनने मे आया है कि 15.9.1982 को क्लास II के बहुत से ऐसे आफिसर्ज है स्टेट के अन्दर, जिनकी पाच पांच साल की सर्विस हो गई है लेकिन वे आज भी टैम्पोरेरी है तो मै दरखासत करना चाहता हू कि सरकार को ऐसी ऐम्पालाईज की सर्विस को भी उसी तरह परमानैन्ट करना चाहिए जिस तरह क्लास III ऐम्पालाईज की सर्विस को किया है।

अध्यक्ष महोदय दूसरी बता मै यह कहना चाहता हू कि एम0 एल0 एज0 होस्टल आपके कंट्रोल के नीचे है। यह एक तरह से हमारा घर है और उसके मालिक आप है। लेकिन वहा जब हम

आते हैं तो हमें रिस्पैक्ट से ट्रीट किया जाना चाहिए। वहाँ कल मैं अपनी कार जब पोर्च के थोड़ा आगे खड़ी करने लगा तो एक सिव्क्योरिटी गार्ड ने कहा कि आप यहाँ से कार हटा लीजिए। मैं उनसे कहा कि ठीक है आपने जहाँ कार खड़ी करने का प्रबन्ध किया है मैं वही कार खड़ी कर देता हूँ लेकिन यह देख लेना कि यहाँ किसी और की कार खड़ी नहीं होगी। खैर वह आदमी अच्छा था और उसने बड़ी तमीज से बात की। मैंने भी राउन्ड अबाउट के पास जहाँ उसने कार खड़ी करने को कहा कार खड़ी कर दी। सबसे मेरे पास फिर एक आदमी आया और कहने लगा कि क्या एच0वाई0एच0 कार आपकी है? मैंने कहा हाँ। वह कहने लगा कि वहाँ से हटनी चाहिए क्योंकि हमारे आई जी0 साहब आने वाले हैं। मैंने कहा कि वहाँ तो बहुत जगह है, दिककत वाली कोई बात नहीं है आई0जी0 साहब आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन वह कहने लगा कि वहाँ से कार हटनी ही चाहिए क्योंकि वहाँ हमने कारें न रखने का फैसला किया। इस पर मैंने कहा कि ठीक है मैं नहाँ धोकर तैयार होकर वहाँ से कार हटा दूँगा कहने का मतलब यह है कि पार्किंग प्लेस में भी कार खड़ी होने के बाद यह हालत है (विघ्न) स्पीकर साहब मैंने यह बात आप को जो होस्टल इन्चार्ज है उसने कही थी मैंने आप को यहाँ भी टेलीफोन किया था उस टाइम आप बाथरूम में थे। इतनी देर में मझे फिर कहा गया कि यह से कार जल्दी हटाओ वरना हम टायर पक्कर कर देंगे। इस तरह की बदतमीजी की बातें व कई बार करते हैं अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि हमारा तो एम0एल0एज0

होस्टल है उसकी बाऊडरी के बाहर यदि सी०आर०सी० रहे तो कोई दिक्कत वाली बता नहीं हैं वे सिक्योरिटी प्वायट औफ व्यू से चैकिंग करे । उसमे कोई एतराज की बात नहीं हैं । वह वाजिब बात है । लेकिन हमारा स्टाफ जब हमे आईडैटिफार्ड कर दे, उसके बाद सी०आर०पी० वाले हमसे कोई बात करे । दूसरे विज इन एम०एल०एज० होस्टल हमारी पुलिस होनी चाहिए जो हरेक एम०एल०एज० को जाने । सी०आर०पी० पुलिस के लोग होस्टल के अहाते मे नहीं रहने चाहिए । We feel humiliated about it.

श्री अध्यक्ष: आज भाम को मै वहा जाऊगा और इस बारे मे बात करूगा ।

चौधरी कुन्दन लाल: स्पीकर साहब, अभी हमारे अपौजी ान के भाई मगरमच्छ के आसू बहा कर गये है, मगर उनको यह पता नहीं कि हमारे हरिजन भाईयो और बैकवर्ड क्लास के भाईयो के साथ क्या क्या अत्याचार हुए हैं हम लोग मोखरा गांव मे जलसे मे गये थे । उसमे हमारे श्री धर्मपाल एम०पी० चौधरी , राजेन्द्र सिंह मिरिनस्टर, कर्नल राव सिंह मिनिस्टर और जीन्द जिले के काग्रेस अध्यक्ष बाबू दयाकृष्ण थे । मै भी उनके साथ ही गया था लेकिन उस जलसे के इन लोगो ने जो हुल्लडबाजी और हमारे बेइज्जती की उसकी कोई इन्तहा नहीं थी । इसी तरह से हमारे बैकवर्ड क्लास मे और हरिजनों की गिरावड गांव मे बेइज्जती की । एक हरिजन रामदासियों ने झडा लगा लिया उसकी भी बेइज्जती की, मारपीट की । जब हमारे पास इस बारे मे

िकायत आयी तो हम वहा पर पहुचें । वहा पर पहुचने पर चौधरी देवी लाल के पोते ने और दाढी वालो ने जो चौटाला से आये थे, मेरे लडके तथा गनमैन की पिटाई की । अगर हम लोग भान्ति से कम लेते है तो हमारे लोगो के साथ ऐसा व्यवहार होता है । अगर हमारे साथ गनमैन ने होता तो इससे भी बुरी होती ।

श्री लछमन सिंह: अगर गनमैन होते हुए भी पिटाई हो गई तो फिर गनमैन का क्या फायदा ?

चौधरी कुन्दन लाल: अगर आप मौके पर होते तो उस वक्त आपको पता चलता । हमारी एक महिला वर्कर जो धानक बिरादरी से थी, उसने हिम्मत करके उस झडे को लगाया । उसके साथ भी मार पीट की गई । इसी तरह से मौखरा गांव के आदमियों ने हमारे हरिजन और बैकवर्ड लोगो को पीटा और उन्हे घरों से बाहर तक नही निकलने दिया । हमारे साथ टेकनपुर गांव मे ऐसा ही हुआ । यह हालत है इन लोगो की ।

श्री अध्यक्ष: आप खत्म करे ।

चौधरी लीला कृष्ण: स्पीकर साहब, मैने भी आज सुबह एक काल अटैन् इन मो इन आप की सेवा मे पे । की थी । चार और पांच अगस्त के बीच की रात को हिसार जिले मे बडे जोर की वर्षा हुई जिस से फसलों तथा मकानो को काफी नुकसान हुआ । खासतौर पर फतेहबाद तहसील मे ज्यादा नुकसान हुआ । यह मेरी मो इन एडमिट हुई है या नही ?

श्री अध्यक्ष: इस बारे में अभी इस तरह की मोशन का जवाब आ रहा है आपको उस समय सवाल पूछवा देंगे।

राजस्व राज्य मंत्री द्वारा – जिला महेन्द्रगढ़ और भिवानी में फसल के हुए नुकसान सम्बन्धी।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मेम्बरज सर्वश्री निहाल सिंह, सुरेन्द्र सिंह, एम0एल0एज0 के काल अटैन्शन मोशन के नोटिस नम्बर 1-2 जो कि डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ और भिवानी में औप्स के नुकसान एटसैटरा के बारे में थे उस पर आज मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट देने के कहा था। मिनिस्टर साहब अब अपनी स्टेटमेंट दे दें।?

राजस्व राज्य मंत्री(श्री लछमन दास अरोडा) माननीय सदस्यों ने पिछले पांच वर्षों में जिला महेन्द्रगढ़ में अपर्याप्त वर्षा एवम जिला भिवानी में भारी वर्षा के कारण से खरीफ की फसल को हुई हानि की और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इन जिलों की वर्तमान वास्तविक स्थिति नीचे वर्णन की जाती है।

जिला महेन्द्रगढ़

यद्यपि व्यावहारिक तौर पर सारे हरियाणा राज्य में वर्षा लगभग एक पखवाड़ा देर से हुई, तथापि अगस्त 1985 के अन्त तक तहसील नारनौल में वर्षा नार्मस से 103.8 मि0 मि0 अधिक और तहसील महेन्द्रगढ़ में नार्मल वर्षा 8.81 मि0 मि0 अधिक वर्षा हुई। परन्तु रिवाड़ी तहसील में अगस्त 1985 के अन्त तक वर्षा सामान्य से 30.5 मि0मि0 कम हुई थी। तहसील रिवाड़ी में सामान्य

से कम हुई वर्षा का व्यावहारिक रूप से खड़ी खरीफ फसलों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसके विपरीत, मास सितम्बर के तीसरे सप्ताह के दौरान हल्की बौछाड़ खड़ी खरीफ फसलों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है और आगामी रबी ऋतु में बेहतर फसल के लिये भी सहायक होगी। महेन्द्रगढ़ जिले की प्रमुख खरीफ फसल बाजरा है निर्धारित 1.50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लक्ष्य की तुलना में इस समय 1.35 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फसल हुई है जो कि निर्धारित लक्ष्य का 90 प्रतिशत बनता है। तथापि रिपोर्ट है कि जिले के कुछ जिले के कुछ इलाके में जुलाई महीने के अन्तिम पखवाड़े में लगातार वर्षा होने के कारण बाजरा फसल की पैदावार पर कुप्रभाव पड़ा है। सरकार द्वारा सूखा जैसी आपदाओं से प्रभावित किसानों की कठिनाईयों को दूर करने वाले आवेदन पत्र उठाए जाते रहे हैं इस समय श्री उपाध्याय पदासीन हुए। रबी 1984-85 के दौरान सूखे की स्थिति से खड़ी फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा था और किसानों द्वारा चालू खरीफ की फसलों को उगाने हेतु साहायता देने के उद्देश्य से खाद की खरीद पर 25 प्रतिशत की दर से सबसिद्धी उपलब्ध करने के लिए इस जिला को 15.25 लाख रुपये की राशि पहले ही अलाट की जा चुकी है इसी प्रकार सस्ते भाव पर खाद उपलब्ध करने के लिए रबी 1982-83 में 27.53 लाख रुपये खर्च किए गए क्योंकि पिछली खरीफ में सूखे के कारण से किसानों को नुकसान हुआ था। इसी प्रकार सस्ते भाव पर खाद उपलब्ध करने के लिए रबी 1981-82 में भी 15.18 लाख

रूपए खर्च किए गए थे। कथित वर्षा में महेन्द्रगढ़ जिले में भूमि संरक्षण स्कीम चलाने के लिए 4.50 लाख रूपए अलाट किए गये।

(2) जहां तक सरकारी एवम बैंको के कर्जों की वसूली को स्थापित करने बारे माननीय सदस्य की मांग का प्रश्न है, यह गिरदारी में देर पाये जाने वाली फसल पर निर्भर करेगा जो सामान्य तौर पर पहली अक्टूबर को आरम्भ होती है और परिणाम मालूम होने पर इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। सरकार जरूरतमंद किसानों को चारा तकाबी भी उनकी आवश्यकता अनुसार देगी। इसी तरह यह भी आवश्यक है कि किसानों द्वारा अगली रबी फसल उगाने के लिए आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किए जायें। इस उद्देश्य से विभिन्न रबी तेल बीजों और दालों की फसलों के लिए 200/- रूपए प्रति क्विंटल की दर से प्रमाणित बीजों पर सबसिडी उपलब्ध की जा रही है। और जिला महेन्द्रगढ़ के लिए पर्याप्त स्टॉक का प्रबन्ध किया गया है गन्दम और जौ के प्रमाणित बीज भी क्रमशः 20 रूपए एवम 50 रूपए प्रति क्विंटल की दर से सबसिडी के तौर पर उपलब्ध किये जायेंगे। यदि आवश्यक समझा गया तो रोजगार कार्यों के लिए अतिरिक्त धन राशि उपलब्ध की जाएगी। किसानों को अल्पकालीन ऋण के रूप में आसानी से सहकारी कर्जें दिलाने के लिए भी प्रयत्न उठाये जा रहे हैं।

जिला भिवानी

3. यद्यपि भिवानी जिले में वर्षा लगभग एक पखवाडा देर से आरम्भ हुई तथात्ति जिले में जुलाई 1985 के दूसरे सप्ताह में वास्तविक वर्षा सामान्य से अधिक थी बाजरा जिला भिवानी की मुख्य फसल है और 2.35 लाख हैक्टर क्षेत्र के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वास्तविक फसल लगभग 1.90 लाख हैक्टर क्षेत्र में बोई गई है जिले के कुछ भागों में जुलाई के दूसरे पखवाडे में लगातार वर्षा से बाजरे की बढौतरी पर बुरा प्रभाव पडा जिसके फलस्वरूप किसानों को फसल दोबारा बोनी पडी । अगस्त के तीसरे सप्ताह में लगातार और रुक रुक कर हुई वर्षा के कारण से खडी फसलों में सुधार होने की सम्भावना है और यह जिले में रबी की फसलों को विशेष कर चना और तेल बीजों को उगाने में भी लाभदायक सिद्ध होगी ।

कुछ अधिक प्रभावित गावों में विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं जिसका परिणाम इस मास के अन्त तक मालूम हो जाएगा । इसलिए सहकारी कर्जों के स्थगन हेतु आवश्यक कदम इस गिरदावरी और सामान्य गिरदावरी जो पहली अक्टूबर से आरम्भ होगी, के फलस्वरूप दिये जाने वाली फसल की स्थिति के आधार पर उठाये जायेंगे । तथात्ति सरकार प्रभावित किसानों को चारा तकावी दे देगी विभिन्न रबी फसलों के लिए सस्ती दरों पर प्रमाणित बीज उपलब्ध करने के लिए भी पर्याप्त प्रबन्ध किये जा रहे हैं जिला भिवानी को पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी पग उठाये जा रहे हैं ।

4. अन्त मे मै सदन के सदस्यो को यह वि वास दिनाना चाहूगा कि सरकार किसानों की जरूरतो के लिए पूरी तरह जागरूक है और प्रभावित किसानों को अधिक से अधिक सम्भव सहायता देने से कोइ कसर बाकी नहीं छोडी जाएगी। इस के अतिरिक्त सभी क्षेत्रो मे भूमि जोतकर तथा आवियाना की मुआफी भी निर्धारित दरों के अनुसार दी जायेगी व जो भी और सहायता जैसे तकावी, सहकारी एवम अन्य कर्जों का स्थगन, अगली फसलो के लिए इनपुटस उपलब्ध करना इत्यादी फसलों का सही नुकसान मालूम होने पर दी जायेगी।

श्री निहाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, गिरदावरी के बाद साबित हो जाएगा कि फसल की बीजाई ही नहीं हुई है। उस इलाके मे जहा पर बीजाई भी नहीं हुई है। उसके इलाके मे जहा पर बीजाई भी नहीं हुई है। वहा पर कर्ज तो मुबलवी किए ही जाए। इसके अलावा कर्जों के ऊपर जो इन्ड्रैस्ट है, वह भी राईट आफ किया जाए। इसके बारे मे मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि लोगो को रोजगार देने के लिए कौन सी स्कीम है जिसके तहत उनको रोजगार मुहैया किया जाएगा? जहा पर फसल फेल हुई है क्या इस बारे मे मंत्री जी को बताने की कृपा करेगे क्योंकि उन्होंने अपने जवाब मे इस बारे मे कुछ भी नहीं कहा है।

श्री लछमन दास: अभी हमारे माननीय सदस्य मे जो इन्ड्रैस्ट वेव आफ करने के बारे मे बात कही है मै उसके बारे मे

बताना चाहूंगा । जहा तक इन्ट्रैस्ट का सवाल है, सारा पैसा तकरीबन बैंको बगैरा का है हम इसके लिए यह विचार कर रहे है कि रिपोर्ट आने के बाद हम उनको इस बारे मे कुछ सहूलियत देने की कोशिश करे। जहा तक लोगो को रोजगार को एन0आर0ई0पी0 के तहत दिया है जिससे वहा पर लोगो को काम मिलेगा । इसके अलावा 14 लाख रुपया इसके तहत हमे वर्ल्ड बैंक ने भी दिया है ।

श्री निहाल सिंह: जो नई रबी का आप रही है उसके लिए लोगो को ज्यादा पानी की सुविधा देने के लिए, नहरी पानी देने के लिए, बिजली बगैरा प्रायरिटी बेसिज पर देने के लिए कोई योजना बतायेगे । अगर हा तो वह क्या होगी?

श्री लक्षमन दास: यह तो हमने अपने जवाब मे डिटेल मे बता दिया है कि हम उनको बिजली और नहरी पानी बगैरा देने मे प्रैफरेंस देगे ।

श्री निहाल सिंह: किस किसम का प्रैफरेंस देगे ?

श्री लक्षमन दास: रिपोर्ट आने के बाद सारी स्कीम बनाकर आपके सामने रखेगे । हम हर हालत मे उनको प्रैफरेंस देगे ।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने यह बताया है कि 20 लाख रुपया एन0आर0ई0पी0 के तहत दिया गया है मैं यह जानना चाहता हू कि उसमे किस किसम

की मजदूरी के काम होंगे। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूँ राव निहाल सिंह जी ने कहा है कि बिजली और पानी के बारे में उस इलाके को ज्यादा प्रैफरेंस मिलना चाहिए ताकि रबी की फसल की बिजाई भी हो सके। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे इलाके में खासकर भिवानी जिले में बहुत सा इलाका ऐसा है जिसमें टयूबवैल का पानी लगाता है और बहुत से हमारे किसान भाईयों ने टयूबवैल कलैक्टिवान्स के लिए दरखास्तें भी दे रखी हैं जो पैडिंग पडी हैं। बिजली बोर्ड का एक सरकुलर है कि जिस किसान ने दरखास्त दे रखी है और वह कनैक्टिवान्स मिल जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, यह बहुत ही मुश्किल बात है। किसी किसान के कनैक्टिवान्स के लिए 5 खम्बों की जरूरत पडती है और किसी के लिए ट्रांसफर की जरूरत पडती है कोई भी किसान यह सब सामना अपना खरीद कर दे नहीं सकता। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह बिजली बोर्ड के अधिकारियों से बात करके उस इलाके में जा गिरदावरी यह साबित कर दे कि वहां पर वाकई बहुत नुकसान हुआ है 70 से 80 फीसदी तक नुकसान हुआ है उस सरकुलर को वेब आफ करने की कृपा करे और बिजली बोर्ड की तरफ से उनको कनैक्टिवान्स जल्दी दिया जाए।

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय जहां तक बरसात की वजह से फसलों के नुकसान का ताल्लुक है हम उसके बाकायदा पहली अक्टूबर से गिरदावरी शुरू करने जा रहे हैं गिरदावरी की रिपोर्ट आएगी, उसके आधारों पर बाकायदा नार्मल

बने हुए है कायदे कानून के मुताबिक उनको रियासत दी जाएगी। एक बात सुरेन्द्र सिंह जी ने ठीक कही कि जहा पर किसान की फसल बरबाद हो गई है अगर वहापर भी किसान को कनैक्शन मिले तो कोई अच्छी बता नहीं है ऐसे एरियाज मे हम को निर्णय करेगे कि कुछ प्रायरिटी के आधार पर उनको प्रायरिटी दिलाकर कनैक्शन दे। हम कितने दिला सकेगे, यह तो बोर्ड से बैठ कर बात करने के बाद ही पता चलेगा।

श्री निहाल सिंह: मान लो कोई किसान पैसा भी भर देता है फिर तो उसको कनैक्शन मिलना ही चाहिए।

चौधरी भजन लाल: यह बोर्ड का मामला है हम उनसे बताचीत करके इस बात की को निर्णय करेगे कि उनको प्रायरिटी के आधार पर कुछ कनैक्शन मिल जाए।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात के लिए और अपनी सरकार से दरखास्त करूंगा। उस इलाके मे जहा पर नहरी पानी भी अब तक नहीं गया है, थोडा सा ज्यादा पानी भी दे ? क्योकि कुछ नहरे ऐसी है जो 12 मासी नहीं है। उन नहरों मे डी सिलटिंग बडी देर की ड्यू है। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थन करूंगा कि ऐसी नहरो मे जहा बरसात नहीं हुई है और डीसिलटिंग भी ड्यू है वहा डी सिलटिंग करवा दे। इससे वहा के लोगो को मजदूरी भी मिलेगी और नहरो का काम भी हो जाएगा। मंत्री महोदय ने बताया है कि 20 लाख रूपया देकर हम काम

करवा रहे हैं एक तो नहरों की डी सिलटिंग का काम करवा दें और दूसरे नहरों में कुछ पानी चलवाने की कोशिश करें।

चौधरी भजन लाल: डिप्टी स्पीकर साहब, जहाँ तक पानी का ताल्लुक है आप जानते हैं हमें सारे हरियाणा को देखना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ नहरों में पानी की कमी है। पिछले दिनों एक नहर की एक साइड की पट्टी गिरने की वजह से तकरीबन एक महीने तक नहर लगातार बन्द रही। बहुत से एरियाज जिनमें हिसार और सिरसा भी शामिल हैं वो भी हमें पानी नहीं दे पाए हैं फिर भी हमें यह कोशिश करेगी कि एक पानी, जिससे बाजरे का खड़ी फसल पक सकती है वह उनको अवश्य मिल जाए। इससे बाजरे की फसल जो खड़ी है पक जाएगी और चना भी बोया जा सकेगा। अगर हम एक बार पानी दें तो इसमें दोनों काम चल सकते हैं जो तक महेन्द्रगढ़, भिवानी, हिसार और सिरसा आदि एरियाज का सवाल है, इन एरियाज में भी हमें कोशिश करेगी कि नहरों में ज्यादा पानी चलाए ताकि वहाँ पर चने और सरसों की फसल बोई जा सके और जो खड़ी फसल है वह पक सके।

चौधरी लीला कृष्ण: डिप्टी स्पीकर साहब, जैसे तो मेरा मोर्चा भी एडमिट होना चाहिए लेकिन चूँकि आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दे दिया है मैं यह बताना चाहता हूँ कि 4-5 तारीख के बीच की रात फतेहबाद, हिसार और सिरसा के इलाकों के लिए एक भयानक रात थी। 24 घंटे तक लगातार मूसलधार बारिश होती रही। हजारों लोग बेघर हो गए। बहुत सी

कालोनीया पानी मे डूब गयी। 10-20 कालोनीयो तो नगर मे थी और मेरे हल्के मे तकरीबन तमाम गांवो मे कोई कच्चा मकान नही बचा। हम मुख्य मंत्री महोदय के इस बता के आभारी है कि उन्होने है कि इलाके का दौरा किया और केवल 400 रुपए कच्चे मकान के लिए और 500 रुपए पक्के मकान के लिए देना निर्धारित किया लेकिन क्या आप यह नही समझते कि यह एक मजाक है ? इतना बडा नुकसान हुआ है कि लोगो की झोपडी, लोगो के कच्चे मकान और यहा तक की पक्के मकान नजर ही नही आते कि कहा पर थे। मै यह मानता हू कि राहत कार्य हुए है लेकिन लोग अब भी एग्जिस्टैस के लिए तडफ रहे है मै मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोधा करुगा कि मेरे कुछ सुझाव है उन पर गोर फरमा ले। पहला तो यह है कि जो ग्रान्ट उन मकानों के लिए मजूर की गई है, यह बहुत थोडी है इसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा वहा पर बाढ की स्थिति पैदा हो गई थी करोडो रुपए की फसल तबाह हो गई है उनको मुआवजा दिया जाए। यह काम वार लैवन पर किया जाए। जिन लोगो ने कर्जे ले रख है चाहे वह नै एनेलाईज्ड बैंको के लिए हो, चाहे कोआप्रेटिव बेको से लिए हो, वह कम से कम मुलतबी किए जाए और उनको कुछ सूद के मामले मे भी छूट दी जाए। इसके अलावा आबपा गी के लिए चूकि हमारे हल्के मे टयूबवैल बहुत ज्यादा तरह से का त कर सके। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है

16.00 बजे

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि तीन जिलो मे बरसात एकदम ज्यादा होने की वजह से काफी नुकसान हुआ है हिसार , सिरसा और जीन्द जिलो मे तकरीबन 94 हजार मकान कच्चे और पक्के मिलाकर गिर गये थे डिप्टी स्पीकर साहब, चार सौ रूपया कच्चे मकान के लिए दिया गया और पांच सौ रूपया पक्के मकान के लिए दिया गया । चार सौ रूपया या पांच सौ रूपए से क्या बनता है यह हम अच्छी तरह से जानते है 91 लाख रूपया अब तक हम सहायता के रूप मे भेज चुके है और 50 लाख रूपया और भेजने जा रहे है । चार सौ रूपया थोडा है इस चीज को देखते हुए हमने भरत सरकार को लिखा है कि पांच हजार पक्के मकान के लिए और अढाई हजार रूपया कच्चे मकान के लिए सहायता के रूप मे मिलना चाहिए । भारत सरकार से उस चिट्ठी का जवाब नही आया है । हम भारत सरकार से बातचीत करेगे । भारत सरकार जितना पैसा देगी सारी का सारा पैसा इन लोगो की मदद के लिए हरियाणा सरकार भिजवाएगी ताकि गरीब लोगो की सहायता हो सके । डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बताय यह कही गई कि जिन किसानो ने बैंको से कर्जा लिया हुआ है वह मुलतवी होना चाहिए । इस बारे मे डिप्टी स्पीकर साहब मै यह कहना चाहता हू कि ज्यो ही गिरदावरी की रिपोर्ट आएगी, हम कोि । । करेगे कि जिन किसानो ने बैंकों से कर्जा ले रखा है वे बैंक के कर्ज अगली फसल तक मुलतवी कर दे ताकि किसानों की कुछ मदद हो सके ।

सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेटस फर्स्ट इन्सटालमेंट 1985-86 पर
चर्चा तथा मतदान

- (I) राज्य के राजस्व पर प्रभारित खर्च के अनुमानों पर चर्चा।
- (II) अनुपुरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री उपाध्यक्ष: अब वर्ष 1985-86 के सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेटस फर्स्ट इन्सटालमेंट पर डिस्कान होगी। पहली प्रैक्टिस के मुताबिक और हाउस का टाईम सेव करने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई all demands will be deemed to have been read and moved. आनरेबल मैम्बरज किसी भी डिमांड पर डिस्कान कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे उस डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं डिस्कान के बाद डिमांडज हाउस की वोट के लिए पुट की जाएगी।

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2000000 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charge that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1986 in respect for Demand No. II Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3800000 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charge that will come in the course of payment for the

year ending 31st March 1986 in respect for Demand No. 16
Development

That a supplementary sum not exceeding Rs.6500000 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charge that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1986 in respect for Demand No. 25 No. 25 Loans and Advances by State Government.

श्री भले राम: डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने इस हाउस से दो करोड़ छ लाख रुपया सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स की भावना में मांगा है मैं डिमान्ड नम्बर 11 जो अर्बन डिवेलपमेंट की डिमांड है के बारे में बोलना चाहता हूँ।

Finance Minister (Shri Sagar Ram Gupta) : I would like to make one point. This is one demand No. 8 which is a charged item and on that demand there will be discussion only and not voting.

श्री भले राम: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस डिमान्ड द्वारा बीस लाख रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, वह मांगा है। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा में बहुत सारी लोकल बौडिज हैं उन सभी का अगर ध्यान रखा जाए तो बहुत अच्छा रहे। कुछ बाहरो तो ऐसे हैं जहाँ पर आज तक बहुत कम पैसा दिया गया है। वहाँ फलड भी आते हैं सिवरेज सिस्टम भी खराब है और रोड्स भी खराब हैं मिसाल के तौर पर हमारा गोहाना बाहर है वहाँ पर जो सिवरेज का सिस्टम है वहाँ बड़ा डिफैक्टिव है। बरसात के

दिनां मे सारी नालिया रूक जाती है। बरसात के पानी को डिस्पोज आफ करने का कोई प्रबन्ध नहीं है इसका नतीजा यह होता है कि नालियो फुल होकर पानी वापिस आ जाता है और इस वहज से गन्दगी बढती है। सिवरेज का जो पानी है वह वाटर स्पलाई की पाईप लाईन मे भी चला जाता है जिससे पीने का पानी गन्दा हो जाता है इस वहज से बीमारी फैलने का डर रहता है इसलिये मेरी सरकार से दरखास्त है कि गोहाना तहसील को ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहिए ताकि इस बैकवर्ड ऐरिया का भला हो सके। वहा हर साल फलड आते है जिसकी वजह से सिवरेज सिस्टम खराब हो जाता है ओर सडके टुट जाती है और नालियो मे पानी भर जाता है हरियाणा सरकार को सारे भाहरो को सुन्दर बनाना चाहिए लेकिन हालत यह है कि आज तक भाहरो को इम्प्रूव करना है गलियों को ठीक करना है और स्लम एरियाज की हालत को सुधारना है इतने बडे काम के लिए बीस लाख रूपया बहुत कम है मै चाहूंगा कि गोहाना को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए जिससे वहा पर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी डिमान्ड 16 नवम्बर है जो हैन्डलूम के बारे मे है। हरियाणा स्टेट हैण्डलूम एण्ड हैन्डीआफटस कारपोरे इन का भोयर कैपीटल बढाने के लिए 38 लाख रूपया इस डिमाण्ड द्वारा मांगा गया है और इसी कारपोरे इन की 65 लाख रूपया पानीपत मे एक फिनिशिंग प्लाट लगाने के लिए दिया जा रहा है डिप्टी स्पीकर साहब, इस कारपोरे इन का जो

औबजैक्टिव था वह पूरा नहीं हुआ है इस कारपोरे इन का औबजैक्टिव यह था कि गांव में जो ट्रेडी इनल जुलाहे हैं जो हाथ से कपडा बनाते हैं उनके बच्चों को सैन्टर्ज खोलकर ट्रेनिंग दें और उनकी मदद करें ताकि वे अच्छा काम कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय हमारे हरियाणा में 113 के करीब सैन्टर्ज हैं जहां पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और एक सैन्टर में पन्द्रह लडकों को ट्रेनिंग दी है। उपाध्यक्ष महोदय इस कारपोरे इन को पांच सात साल बने हो गए हैं लेकिन आज तक इतने थोड़े से लडकों को ही ट्रेनिंग दे पाई है। कारपोरे इन का फर्ज बनता है कि जुलाहों के लडकों को खडिडियों पर ट्रेनिंग देने के बाद उनको कर्जा दें, उनकी खडिडियां लगाने में मदद करें लेकिन यह कारपोरे इन ऐसा नहीं करती। वे लडके कहा जाते हैं इस बात की इस कारपोरे इन को बिल्कुल परवाह नहीं है इस कारपोरे इन का औबजैक्टिव था कि वह इस तरह के लोगों को एम्प्लायमेंट दें लेकिन इस दिना में यह कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि लडकों की ट्रेनिंग के लिए अधिक से अधिक सैन्टर्ज खोले जाएं। ये सैन्टर्ज गांवों में खोले जाएं। पन्द्रह लडकों की बजाये ज्यादा लडकों को दाखिला दिया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, यह देखा गया है कि लडके बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ कर भाग जाते हैं और इसका कारण यह है कि उनको केवल सौ रूपया महीना स्टार्टपैड के रूप में दिया जाता है मैं समझता हूँ कि यह रूपया बहुत थोड़ा है और इसी कारण से वे भाग जाते हैं इसलिए उनका स्टार्टपैड बढ़ाया जाना चाहिए। मेरी सरकार से यह

भी प्रार्थना है कि हैण्डलूम कारपोरे इन को ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहिए और सबसिडी देनी चाहिए। तभी हम हैण्डलूम कारपोरे इन बनाने का औबजैक्टिव अचीव कर पाएंगे। इन भाब्दो के साथ मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि ये डिमान्डज पास कर दी जाए।

चौधरी लीला कृष्ण: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमान्ड नम्बर 25 के बारे में कुछ भाब्द कहना चाहता हूँ। यह पैस सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने दिया है डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा में जितनी उदारता से लोगों को कर्जा दिया जात है मेरे खयाल में किसी और राज्य में इतनी उदारता से कर्ज तथा पे गियां नहीं दी जाती। यह बात भी ठीक है कि इंडस्ट्रीज के लिए सरकार की ओर से काफी साधन जुटाए जाते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐप्लीके इनज पैडिंग रहती है। डिप्टी स्पीकर साहब, आज उधोग का युग है और आज हमारे नौजवानों को आसानी से नौकरी नहीं मिलती। सरकार की तरफ से यह पूरी कोशिश होती है कि अनएम्पलाएमेंट खत्म हो लेकिन फिर भी बहुत नौजवान को उदारतापूर्वक कर्जा दिया जाए ताकि वे इंडस्ट्री लगा सकें और अनएम्पलाएमेंट खत्म हो मैं समझता हूँ इसी तरह से हरियाणा की काया कल्प हो सकती है। इस तरह के बजट में बड़ा चढ़ा कर पैसा रखा जाए जिससे नौजवानों को काम मिले और कोई भी अनएम्पलाएड न रहे। डिप्टी स्पीकर साहब, अनएम्पलाएमेंट से उग्रवाद पनपता है इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये

ऐस्टीमेटस तो मन्जूर होंगे ही लेकिन फ्यूचर के लिए इन मदों में अधिक धन रखा जाए।

वित्त मंत्री (श्री सागर राम गुप्ता): डिप्टी स्पीकर साहब, आज हाउस के सामने बहुत थोड़ी अमाउंट की डिमांड पे 1 की गई हैं एक दो प्वायंटस जो आनरेबल मैम्बरज ने बोलते हुए यहां कहे हैं उस के बारे में अर्ज करता हूँ श्री भले राम जी ने बोलते हुए यह रिफ़ायरेंस की है कि 20 लाख रुपए की राशि स्लमकलीरेन्स के लिए बहुत थोड़ी रखी गई है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यह राशि हमें भारत सरकार ने स्लम क्लीरेन्स के लिए म्यूनिसिपल कमेटिया को बाटने के लिए मिली है यह बात ठीक है कि यह रकम बहुत थोड़ी है इस के साथ ही उन्होंने दूसरी बात यह कही कि गोहाना के अन्दर सीवरेज वाजिब है इस बात को हम देख लेंगे मैं इस बारे में अपने कुलींग पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर साहब से निवेदन कर दूंगा। इस के साथ साथ हैण्डलूम कारपोरेट्स के बारे में भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं भायद उन्होंने इस बारे में पीयूसी के मैम्बर होने के नाते एग्जामिन किया होगा। हो सकता है कुछ कमियां उन्होंने इस में पाई हो लेकिन इस कारपोरेट्स ने कम बहुत किया है और आज हमारे पानीपत के अन्दर हैण्डलूम सैन्टर्ज की जितनी डिवैल्पमेंट हुई है वह सारे हिन्दुस्तान में तो क्या सारी दुनिया में उस की माहुरी हुई है इस के लिए इस कारपोरेट्स का काफी कंट्रीब्यूशन है लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से यह पूरी कोशिश करेंगे कि

इस कारपोरे इन की फव ानिंग मे आगे से सुधार हो और किसी किस्म की कमियां हमे न दिखाई दे। जो छोटी मोटी कमी इस कारपोरे इन की फव ानिंग मे होगी, हम उसे हर सम्भव कोर्ि ा ा से दूर करने का यत्न करेगे। इस के साथ साथ हम यह भी कोर्ि ा ा करेगे कि इस कारपोरे इन के द्वारा देहात के लोगो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे लोग काम सीख कर अपना उधोग धन्धा स्थापित कर सके और अपना पालना पोशण अच्छी तरह से कर सके। वजीफो के बारे मे भी हम पूरी कोर्ि ा ा करेगे और वाजिब हुआ तो हम इस की रार्ि ा को बढा देगे।

इसके साथ श्री लीला कृशण जी ने जो सुझाव दिया है वह बहुत अच्छा सुझाव है। स्टेट की सरकार पूरी तरह से इस कोर्ि ा ा मे लगी हुई है कि इडस्ट्रीज लगाने के लिए प्रदे ा के अन इम्पलायड लोगो को ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध कराया जाए। मै उन को यह बताना चाहता हू कि सरकार नौ जवानो को कर्जो के साथ और दूसरी प्रकार की जितनी भी सहूलियते है वे उपलब्ध कराने की हर सम्भव कोर्ि ा ा कर रही है ताकि प्रदे ा के नौजवानो को अपना काम धन्धा चलाने मे किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पडे। इन भाब्दो के साथ मै निवेदन करूंगा कि इन डिमाडज को पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: अब मै डिमाडंज वोटिंग के लिए पुट करता हूं।

Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs.2000000 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charge that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1986 in respect for Demand No. 11 Urban Development.

The Motion was carried

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3800000 for capital expenditure be granted to the Government to defray charge that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1986 in respect for Demand No. 16 Urban Development.

The Motion was carried

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6500000 for capital expenditure be granted to the Government to defray charge that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1986 in respect for Demand No. 25 Loans and Advances by state Government .

The Motion was carried.

श्री उपाध्यक्ष: अब सदन कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

16.13 बजे

(तत्प चात सदन भानिवार दिनांक 28.9.1985 को प्राप्त
9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)

ANNEXURE

Recruitment made by the Haryana State Cooperative Land Development Bank

***1029. Shri Ram Bilas Sharma.** Will the Minister of State for Cooperation be pleased to State-

(a) the total number of employees working at present on permanent, temporary and daily wages basis in the Haryana State Cooperative Land Development Bank, Chandigarh separately;

(b) the number of class IV employees out of the employees referred in part above together with the names and permanent addresses thereof,

(c) the categorywise number of employees out of the employees mentioned in part a above recruited during the period from May, 1982 to June 1985 and

(d) the criteria adopted for the recruitment of the employees as referred to in part c above ?

Minister of State for Cooperation (Shri Piara Singh):

(a) A statement showing the requisite information is laid on the Table of the House (Annexure A)

(b) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House (Annexure B)

(c) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House (Annexure C)

(d) The appointment were made on the basis of merit and suitability of the candidates

ANNEXURE-A

Total No. of employees working at present in Haryana State Cooperative Land Development land Ltd Chandigarh	No of permanent employees	No of temporary employees	No of employees on daily wages
162	137	25	Nil

ANNEXURE-B

Total	No of the IV Employees	The Names of the Class IV employees	Permanent of Address of Class IV Employees
	1	2	3
	Sr No.	Sarvshri	
54.	1.	Devi Dass	Devi Dass s/o Harwari Lal, Lal Kurti Bazar H.No. 500 Ambala Cantt
	2.	Rama Nand	Rama Nand s/o Jumpha

			Ram VPO Dabwali Distt Sirsa
	3.	Kuldeep Singh	Kuldeep Singh s/o Jai Kishan Dass VPO Meham Distt Rohtak
	4.	Nathu Ram	Nathu Ram s/o kanshi Ram C/o Viadi Days Ram Ex M.L.A Hno 1702, Ward No. 940 Mandi Dabwali Distt Sirsa
	5.	Rampal Yadav	Rampal Yadav s/o Matadin Vpo Mirpur Teh Rewari Distt Mohindergarh
	6.	Puran Chand	Puran Chand s/o Rulia Ram VPO Sultanpur Teh Jagadhri Distt Ambala
	7.	Balbir Singh	Balbir Singh S/o Chandan Singh VPO Bhagwas Teh Rajpura Distt Putiala (Pb)
	8.	Bhagwan Singh	Bhagwan Singh s/o Rattan Chand Vill Seela, Po Sukaru Teh Distt Kangra (H.P)

	9.	Chhote lal	Chhotl Lal s/o Babu Ram, Vill Dhotka Purwa, Po Guauriganj Teh Amethi Distt Sultanpur U.P
	10.	Chandan Ram	Chandan Ram s/o Richhi Ram Vill Mundal Dhura Po Dabra Teh. Ranjkhet Distt Almora U.P
	11.	Chander Singh	Chander Singh s/o Tek Ram Vill Mundal Khurad Teh Hansi Distt Hissar
	12.	Dan Bahadur	Dan Bahadur s/o Harke Bahadur Malang Dands Po Tahun Distt Paipa Nepal
	13.	Ishwar Lal	Ishwar Lal s/o Dhani Ram Vill Nehra, Teh Ranikheta, Distt Almora UP
	14.	Ishwar Singh	Ishwar Singh s/o Rishal Singh VPO Dhaanana Teh Gohana Distt Sonapat
	15.	Daya Nand	Daya Nand S/o Khema Ram, VPO Kanther PO Bhagvi Teh Dadri Distt

			Bhiwani
	16.	Jaswant Ram	Jaswant Ram s/o Gautam Ram VPO Deyyal Teh Ranikher Distt Nenital UP
	17.	Jaswant Singh	Jaswant Singh s/o Duli Chand Choki No. 2 Mushapur Teh Rewari Distt Mohindergarh
	18.	Smt. Jagir Kaur	Jagir Karu w/o Prem chand Vill Paploys Teh & PO Kalka Distt Ambala
	19.	Khushal Singh	Khushal Singh s/o Narain Singh, Vill Dabhara Patiwala Teh Ranikhet Distt Almora U.P
	20.	Laxmi Kant	Laxmi Kant s/o Nirad Baura, Vill Saldha Distt Bankura W. Bengal
	21.	Mauji Lal	Mauji Lal S/o Hiral Lal Nasiranj Mangal Bazar Distt Sahabad Are Bihar
	22.	Moti Ram	Moti Ram s/o Gautam Ram Vill Kankhari Patti PO Devyal H.P.O Ram

			Nagar U.P
	23.	Mehtab Singh	Mehtab Singh s/o Parbhati Ram Vill Nikipur Teh Loharu, Distt Bhiwani
	24.	Mohan Lal	Mohan Lal s/o Mang Ram Shop No. 107 Nai Mandi Adampur Distt Hissar
	25.	Nar Bahadur	Nar Bahadur s/o Bhan Bahadur VPO Kundi Teh Betaid Nepal
	26.	Nagini Dive	Nagini Divi ww/o Bhakhtwar Singh VPO Khuda teh & distt Mujafar Nagar U.P
	27.	Om Bahadur	Om Bahadur s/o Lal Bahadur Vill Angarkhola, P.O Chatti Pani Teh Distt Palpa Napal
	28.	Padam Singh	Padam Singh s/o Balram Singh Vill Machhor Teh Ranikhet Distt Almora UP

	29.	Prem Dutt Chamoli	Prem Dutt Chamoli s/o Kola Nand, Vill Moja Patta, Pata Sarjula Po Gumbo Teh & Distt Garhawal U.P
	30.	Pritem Chand	Pritem Chand s/o Sham Lal VPO Rohla Teh Shahpur Distt Kangra H.P
	31.	Raja Ram	Raja Ram s/o Sukhi Ram Vill Dudshia Bagar Distt Gonda (U.P)
	32.	Ram Murti	Ram Murti S/o Ram Partap Vil Malgoorpur PO Niyanya Taraganj Distt Gonda U.P
	33.	Ram Saran	Ram Sarna s/o Chhotu Singh Vill Gharoli, P.O Kahdor Shapur Teh Oatti Distt Partapgarh U.P
	34.	Ram Bahdur	Ram Bahdur s/o Dan Bahadur VPO Saudhi Distt Beglung Nepal
	35.	Rattan	Rattan s/o Jiya La Hno. 1379 Sector 22 Chandigarh

	36.	Sarbati Devi	Sarbati Devi w/0 Bansi Lal Qrt. No. 1-A Block 7 Sector 24 Chandigarh
	37	Sadhu Ram	Sadhu Ram s/o Ghasitu Ram Vill Bhatiana PO Manohshial Teh Nurpur Distt Kangra H.P
	38.	Man Singh	Man Singh s/o Daljit Singh Vil Nadidhakali PO Pattan distt Batadi Nepal
	39.	Dhan Pal	Dhan Pal s/o Chander Bhan Vill Alewa Teh Distt Jind
	40.	Rakesh Kumar	Rakesh Kumar s/o Amar Chand VPO Thakloh, Teh Jawaiamukhi Distt Kangra.
	41.	Balram	Balram s/o Chet Ram Vill Nandhauri Near Bhuna Teh Fatehabad
	42.	Mange Ram	Mange Ram s/o Burmah Ram VPO Dinod Distt Bhiwani
	43.	Smt Gita Sharma	Gita Sharma w/o Barasham Dutt Sharma Hno. 691 sector 20 A

			Chandigarh
	44.	Iqbal Ahmed	Iqbal Ahmed s/o Bahir Ahmed, Vill Sukhpuri Po Umra Teh F.P Jhirkha Gurgaon
	45.	Karamvir	Karamvir s/o chiranji Lal Vill Manakhpur, Teh Kalka Distt Ambala
	46.	Paras ram	Paras Ram s/o Gajeshwar Singh, Vill Karedawar PO Akari Distt Tehrigarhewt UP
	47.	Ramesh Kumar	Ramesh Kumar s/o Ami Ram, VPo Mohara Teh Ranikhet Distt Almora UP
	48.	Baljeet Singh	Baljeet Singh s/o Sodhi Ram Vpo Balashmand Teh Hissar
	49.	Raj Kumar	Raj kumar s/o Janeshwar Dass, Hno. 46 Sector 20 Chandigarh
	50.	Sobha Singh	Sobha Singh s/o Padam Singh Kothi No. 70 Sector 21 Chandigarh

51.	Jai Karna	Jai Karna s/o Ram Tahal Singh Vill Ranbir Nagar Po Amethi Distt Sultanpur UP
52.	Ali Mohammed	Ali Mohammed Vill Singharlehri PO Punhana Distt Gurgaon
53.	Ram Saware	Raw Saware s/o Shiv Parshad Vil Bodehoya, PO Khaparadi The Bikapur Ditt Falizabad
54.	Hari Bahadur	Hari Bahadur s/o Karna Bhhadur Vill Argha Bagi Daduva Ward No. 3 PO Argha Kuranpani Dist Argha Khanchi Nepal

ANNEXURE-B

Sr No.	Category of Emplyees	Number of Emplyees recruited during the period from May 1982 to June 1985
1.	Law Officers	6

2.	Land Valuation officers	1
3.	Clerks	18
4.	Drivers	2
5.	Peons	16
	Total	43